श्रावण शुक्ल पक्ष-प्रतिपदा, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 39 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांकः म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
13 अगस्त 2026 गुरुवार

आज का मौसम
27.6 अधिकतम
23.1 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

न्यूज विंडो

धार: प्राइवेट बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर, बच्चों समेत दर्जनभर घायल

धार। इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम पीपलखेड़ा के पास सुबह करीब 9 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक करने के दौरान एक निजी बस ने स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल बस में सवार बच्चों सहित दोनों बसों के दर्जनभर से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ओवरटेक के दौरान पर्याप्त जगह नहीं बचने से निजी बस स्कूल बस के पीछे जा भिड़ी।

भूकंप के झटकों से कांपी लेह लद्दाख की धरती, घरों से भागे लोग

लेह। लद्दाख के लेह में आज तेज भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक,सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 दर्ज की गई है। इसकी गहराई 10 किमी. जमीन के नीचे थी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। दूसरा झटका नौ बजकर 54 मिनट पर आया था। हालांकि अब तक भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।

एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी

मुंबई। एनसीपी के नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। जीशान को एक फोन कॉल पर धमकी दी गई। जीशान का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारियों और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी दे दी है। बीते हफ्ते भी जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं साल 2024 में उनके पिता बाबा सिद्दीकी की भी हत्या कर दी गई थी।

पंजाब में बड़ा सड़क हादसा: आप के तीन कार्यकर्ताओं की मौत

हलवारा (पंजाब)। रायकोट-जगरांव रोड पर गांव बस्सियां के पास बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब सवा एक बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पानी से भरे तालाब में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार पांच लोगों में से तीन की मौत हो गई, जबकि दो लोग बाल-बाल बच गए। मृतकों की पहचान बलकार सिंह, विशाल और संदीप के रूप में हुई है। तीनों के आम आदमी पार्टी से जुड़े होने और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के करीबी साथी होने की जानकारी सामने आई है।

जयपुर में बारिश से पेड़ गिरे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से 20 राज्यों में अच्छी बारिश हुई। अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार चार दिनों से तेज बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से 204 सड़कें बंद हैं। राजस्थान के 5 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। जयपुर में 4 घंटे से ज्यादा पानी बरसा। पानी से भरे गड्ढे के कारण बस पलट गई। बारिश और पेड़ गिरने से करीब सात घंटे तक शहर के ज्यादातर हिस्सों में ट्रैफिक जाम रहा। उधर, उत्तराखंड के देहरादून-मसूरी मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़क पर आ गिरा।

आज का कार्टून

फर्टिलाइजर पॉलिसी की खुली पोल ... बढ़ता जा रहा सब्सिडी का बोझ, किसानों के हाथ खाली

खाद के लिए सड़क पर उतर रहे किसान डीएपी है ही नहीं, कहां से दे सरकार

दोपहर मेट्रो पड़ताल पार्ट-1
राजेश सिरोठिया

भोपाल। सावन की बारिश ने मध्यप्रदेश के किसानों के चेहरे पर उम्मीद लौटाई है, लेकिन खेतों में पानी पहुंचते ही खाद की कतारों ने उस उम्मीद पर सवाल खड़ा कर दिया है। रायसेन में डीएपी के लिए किसानों का सड़क पर उतरना महज एक जिले की प्रशासनिक समस्या नहीं है। यह उस खाद नीति की पोल खोल रहा है, जिसमें सरकार सब्सिडी का बोझ बढ़ाती जा रही है, लेकिन किसान को उसकी जरूरत के समय खाद नहीं मिल पा रही। बुधवार को रायसेन कृषि मंडी में डीएपी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने तालाबंदी कर दी। प्रशासन और किसानों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एसडीएम पर पानी फेंकने की घटना तक सामने आई। बरेली में भी किसानों का आक्रोश दिखाई दिया।

सवाल सीधा है कि जब डीएपी उपलब्ध ही नहीं है तो किसान को सब्सिडी किस बात की दी जा रही है? कागज पर खाद सस्ती हो सकती है, लेकिन खेत में खाद तभी पहुंचेगी जब गोदाम में स्टॉक हो, कंपनी आपूर्ति करे, सरकार भुगतान करे और वितरण व्यवस्था किसान तक पहुंचे। यहीं से इस संकट की असली कहानी शुरू होती है।

दोपहर मेट्रो की पड़ताल में सामने आया है कि इस समय किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यूरिया से ज्यादा डीएपी को लेकर है। निजी दुकानों से लेकर सहकारी समितियों तक इसकी उपलब्धता पर सवाल हैं। विकल्प के रूप में एनपीके मौजूद है, लेकिन उसकी कीमत और उपलब्धता अलग समस्या है। एनपीके की क़ीमत 12 सौ से बढ़ाकर 2100 रुपये बोरी कर दी गई । लेकिन बाज़ार में इसकी क़ीमत 2400 रुपये के क़रीब किसानों को देना पड़ रही है । डीएपी की समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि किसान इसे बोवनी के शुरुआती चरण में चाहता है। खाद कुछ दिन बाद मिले तो उसकी उपयोगिता का सवाल भी खड़ा हो जाता है।

खाद की जरूरत कैलेंडर देखकर नहीं, खेत देखकर पैदा होती है।

खाद के लिए ऐसी आपाधापी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चित्र रायसेन के बरेली का।

महंगे दामों पर ब्लैक में बिक रहा है एनपीके, रायसेन की मंडी में हो चुकी है तालाबंदी

छह साल बाद भी संकट जस का तस

मई 2021 में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बाद केंद्र ने डीएपी की प्रति बोरी सब्सिडी 500 रु से बढ़ाकर 1,200 रु कर दी थी और करीब 14,775 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाने की घोषणा की थी। लेकिन छह साल बाद भी सवाल वही है। सरकार का खर्च बढ़ रहा है, फिर किसान की परेशानी क्यों नहीं घट रही? 2026 के खरीफ मौसम के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी का अनुमानित बजट करीब 41,534 करोड़ रूपए पहुंच गया है, जो पिछले खरीफ से लगभग 4,317 करोड़ अधिक है। यानी सरकार की तरफ से पैसा बढ़ रहा है। मगर किसान की कतार भी बनी हुई है।

विरोधाभास है जांच का विषय: खाद उद्योग से जुड़े सूत्रों और उपलब्ध आंकड़ों की पड़ताल यह सवाल उठाती है कि सब्सिडी भुगतान और आपूर्ति व्यवस्था में घरेलू कंपनियों की देनदारियों तथा आयातित खाद की तत्काल जरूरत के बीच सरकार ने किसे प्राथमिकता दी। यदि घरेलू कंपनियों के सब्सिडी भुगतान में देरी होती है तो उनकी कार्यशील पूंजी दबती है। दूसरी तरफ आयातित डीएपी की जरूरत तत्काल पूरी करनी पड़ती है। ऐसे में सरकार के सामने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान और घरेलू उत्पादन को बनाए रखने के बीच संतुलन का सवाल खड़ा होता है। यही वह जगह है जहां खाद सुरक्षा केवल कृषि मंत्रालय का विषय नहीं रह जाती। यह वित्त, वाणिज्य, विदेश नीति और औद्योगिक नीति का भी सवाल बन जाती है। डीएपी के लिए भारत की निर्भरता आयात और आयातित कच्चे माल पर काफी है। 2025 में उपलब्ध आंकड़ों ने भी दिखाया था कि देश में डीएपी का शुरुआती स्टॉक पिछले वर्षों की तुलना में काफी नीचे था और कंपनियां महंगे आयात के बीच सतर्कता से खरीद कर रही थीं।

हॉर्मुज़ से खेत तक

पश्चिम एशिया के युद्ध ने इस संकट को और जटिल किया है। भारत के डीएपी आयात में मध्यपूर्व की बड़ी भूमिका है और 2026 में वैश्विक डीएपी कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत तक उछाल की रिपोर्ट सामने आई। इसलिए आज रायसेन की खाद की कतार को केवल रायसेन की समस्या समझना भूल होगी ।हॉर्मुज़ में तनाव का असर अगर जहाज पर पड़ता है तो उसकी कीमत अंतत : खेत तक पहुंचती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संकट अपनी जगह है ।सरकार से असली सवाल घरेलू प्रबंधन का है। जब संकट पहले से दिखाई दे रहा था, तो पर्याप्त डीएपी पहले क्यों नहीं पहुंचाई गई? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकती तो बढ़ती सब्सिडी का किसान को वास्तविक लाभ क्या है? रायसेन की सड़क यही सवाल पूछ रही है। अब जवाब सरकार को देना है।

'संसद यूथ पार्लियामेंट 2026'

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज से विधानसभा भवन में शुरू हुई दो दिवसीय 'संसद यूथ पार्लियामेंट ' का उदघाटन किया। कार्यक्रम में 58 से अधिक शहरों के युवा शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को संसदीय प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नीति-निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराना है।

वंदे मातरम के बाद कार्यवाही स्थगित

मानसून सेशन के आखिरी दिन सिर्फ 1 मिनट ही चली लोकसभा

नई दिल्ली। मानसून सत्र के आखिरी दिन आज लोकसभा की कार्यवाही एक मिनट ही चली। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान कराया और इसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में मोदी-शाह समेत पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में आज भी विरोध प्रदर्शन किया। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में विपक्ष नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है।

पूर्व सांसद पर नई एफआईआर दर्ज

जेल में प्रज्वल रेवन्ना के फोन से 90 पोर्न-वीडियो मिले

बेंगलुरु। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल में 90 पोर्न वीडियो मिले हैं। जब्त फोन की फोरेंसिक जांच जारी है। जांचकर्ता फोन में मौजूद वीडियो, तस्वीरों और अन्य डिजिटल डेटा की जांच कर रहे हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि सामग्री कहां से आई और इसका आपराधिक मामले से कोई संबंध है या नहीं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को जेल में छापेमारी की थी। रेवन्ना के पास फोन मिलने के बाद नई FIR दर्ज की गई है। जेल में बंद अंडरट्रायल कैदी प्रताप राय को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।

यूएन की रिपोर्ट में दावा

अलकायदा ने कराया था लाल किले पर धमाका

नई दिल्ली, एजेंसी

लाल किले के पास हुए धमाके में अलकायदा से जुड़े संगठन का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने इस धमाके को अंजाम दिया। इसमें कहा गया है कि एक्यूआईएस अब छोटे-छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है और उसने अपना लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। इससे पहले आई यूएनएससी की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया था। यानी इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लगातार दो रिपोर्टों में दो अलग-अलग आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं। हालांकि, NIA की चार्जशीट में दावा किया गया था कि आरोपी एक्यूआईएस से जुड़े थे।

बांग्लादेश में भी अपने आतंकी सेल बनाने की कोशिश कर रहा एक्यूआईएस

UNSC की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की यह रिपोर्ट 10 अगस्त को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि एक्यूआईएस अब बिखरे हुए छोटे आतंकी संगठन की बजाय एक क्षेत्रीय आतंकी नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है। संगठन ने अपना लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार कर लिया है और अब बड़े समूहों के बजाय छोटे-छोटे, अलग-अलग सेल के जरिए काम कर रहा है।

नशे में पायलट... विकास के दावों के बीच हवा में हांफती यात्री सुरक्षा

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में जो हुआ, उसे केवल 'टर्बुलेंस' कहकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन अब सामने आ रहे तथ्य इस घटना को कहीं अधिक गंभीर बना रहे हैं। 4 अगस्त को AI2379 में अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई गिर गई। विमान में 137 यात्री और आठ क्रू सदस्य थे और 24 लोग घायल हुए। शुरुआत में इसे एयर टर्बुलेंस से जोड़कर बताया गया। बाद में कमांडर ड्रग स्क्रीनिंग में फेल हुआ और फिर दूसरे टेस्ट में मारिजुआना पाए जाने की खबर सामने आई। दोनों पायलटों को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटाया गया है और मामले की जांच हो रही है।

कहना जरूरी है

अनिल शर्मा

ऐसे में सवाल है कि यात्री की जान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या गांजा जैसा नशा करके कोई पायलट कॉकपिट में जा सकता है ? क्या सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया था कि लगभग डेढ़ सौ लोगों की जिंदगी जिसके हाथ में है, वह हर लिहाज से उड़ान के लिए फिट है या नहीं? अगर पायलट के व्यवहार को लेकर पहले से कोई शिकायत थी, अगर वह असामान्य अवस्था में दिख रहा था, अगर उसे ठीक से चलने में दिक्कत थी या कॉकपिट में उसका व्यवहार सामान्य नहीं था, जैसी बातें रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं तो यह किसी एक पायलट की गलती से बड़ा मामला है। यह फिटनेस मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और एयरलाइन की जवाबदेही का मामला है।

क्या एयरलाइन का काम सिर्फ विमान को समय पर उड़ाना है? नहीं। एयरलाइन की पहली जिम्मेदारी यात्री को सुरक्षित पहुंचाना है। मुनाफा, समय की पाबंदी, विमान का अधिकतम इस्तेमाल, सस्ता किराया, सब उसके बाद आते हैं। अगर खर्च घटाने की होड़ में क्रू की निगरानी, मेडिकल फिटनेस, मानसिक स्थिति, ड्रग और अल्कोहल टेस्टिंग अथवा सुरक्षा प्रोटोकॉल कमजोर पड़ते हैं तो सस्ता टिकट यात्रियों को बहुत महंगा पड़ सकता है।

दुनिया के कई देशों में सुरक्षा व्यवस्था कहीं अधिक कड़ी है। अमेरिका में एयरलाइनों को प्री-एम्प्लॉयमेंट, रैंडम, उचित संदेह और पोस्ट-एक्सिडेंट ड्रग टेस्टिंग का ढांचा रखना होता है। 2026 में अमेरिका ने संवेदनशील कर्मचारियों के लिए न्यूनतम रैंडम ड्रग टेस्टिंग दर 25 प्रतिशत और अल्कोहल टेस्टिंग 10 प्रतिशत रखी है। ऑस्ट्रेलिया में मॉडल और भी स्पष्ट है। वहां फ्लाइट क्रू समेत सुरक्षा-संवेदनशील काम करने वाले कर्मचारियों की गैर-घोषित ड्रग और अल्कोहल जांच हो सकती है। अल्कोहल के लिए ब्रीथ टेस्ट और ड्रग्स के लिए ओरल-फ्लूड टेस्टिंग की व्यवस्था है। जाहिर है ,यह तुलना भारत के लिए असहज करने वाली है। यहां तो हालत यह है कि फुकेट से उड़ान भरने से पहले पायलट का ब्रीद एनालाइजर टेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां यह सुविधा ही नहीं थी। ऐसे में एयर समझ लें कि इंडिया यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। यह भी हास्यास्पद कहा जाएगा कि हम एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाने, नए टर्मिनल बनाने और विमानन क्षेत्र को तेजी से विस्तार देने की उपलब्धियां गिनाएं, लेकिन सुरक्षा के बुनियादी सवाल पर आकर व्यवस्था हांफने लगे। हवाई अड्डे बढ़ाना विकास है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना शासन की जिम्मेदारी है।

विदेशी ऑपरेटरों के लिए खुले रास्ता

एक और बड़ा सवाल एयरलाइन प्रतिस्पर्धा का है। क्या भारत को अब यह गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए कि घरेलू विमानन बाजार में अधिक सक्षम विदेशी ऑपरेटरों के लिए रास्ता खोला जाए? प्रतिस्पर्धा सिर्फ किराया घटाने के लिए नहीं, बल्कि सेफ्टी स्टैंडर्ड, ट्रेनिंग, क्रू मैनेजमेंट और जवाबदेही के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन विदेशी कंपनियों को अनुमति देना भी समाधान तभी होगा, जब नियामक सभी कंपनियों पर समान कठोर सुरक्षा मानक लागू करे। एक विमान 300 फीट नीचे जाता है तो केवल विमान नहीं गिरता, लोगों का भरोसा गिरता है। यात्री विमान में टिकट खरीदकर बैठता है, अपनी जिंदगी सिस्टम के हवाले करता है। बदले में उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सुरक्षित यात्रा। यह मांग सुविधा नहीं है। यह उसका अधिकार है।

आईसीयू से इमरजेंसी और सोनोग्राफी सेंटर तक कई जगह जलभराव, पानी रोकने के लिए रखनी पड़ीं बाल्टियां

जेपी अस्पताल में बारिश ने खोली इंतजामों की पोल, छत से टपका पानी

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी के जेपी अस्पताल में मंगलवार शाम हुई बारिश ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। अस्पताल के कई हिस्सों में छत से पानी टपकता रहा। सी ब्लॉक की पहली मंजिल पर आईसीयू के पास लगातार पानी गिरने से प्रबंधन को नीचे बाल्टियां रखनी पड़ीं। सी ब्लॉक की सीढ़ियों में भी पानी जमा हो गया, जिससे मरीजों, स्वजन और स्टाफ के लिए फिसलने का खतरा बना रहा।

ए ब्लॉक की पहली मंजिल पर भी छत से पानी टपकता मिला। मरीजों और परिजनों के बैठने की जगह पर पानी जमा होने से लोगों को दूसरी जगह तलाशनी पड़ी। लकड़ी की कुर्सियां और बेंच भी पानी से भीग गए। इमरजेंसी वार्ड में भी छत से पानी टपकता रहा। महिला वार्ड के भीतर जलभराव होने से भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हुई। अस्पताल की पुलिस चौकी और हीमोफिलिया वार्ड के बाहर भी पानी जमा रहा। सोनोग्राफी सेंटर और पंजीयन केंद्र तक पानी पहुंच गया। यहां रखे दस्तावेज भीग गए। बारिश के दौरान अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों में पानी टपकने और जमा होने से भवन की छत और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए।

सीढ़ियों से वार्ड तक, हर तरफ पानी

आईसीयू के पास छत से पानी टपकने के कारण बाल्टियां रखनी पड़ीं। सी ब्लॉक की सीढ़ियों में पानी जमा होने से आवाजाही मुश्किल रही। ए ब्लॉक, महिला वार्ड और हीमोफिलिया वार्ड के बाहर भी जलभराव हुआ। मरीजों और उनके परिजनों को पानी से बचते हुए रास्ता तय करना पड़ा। बुजुर्ग और गंभीर मरीजों के लिए गीली सीढ़ियां और फर्श खास तौर पर परेशानी का कारण बने।

दस्तावेज भी भीगे, मरीज हो रहे परेशान

सोनोग्राफी सेंटर, पंजीयन केंद्र में पानी पहुंचने से वहां रखे दस्तावेज गीले हो गए। मरीजों के बैठने वाली जगहों पर पानी जमा होने से लोगों को जगह बदलनी पड़ी। इमरजेंसी वार्ड में भी छत से पानी टपकता रहा। मरीजों का कहना था कि बारिश के दौरान अस्पताल में कई जगह ऐसी स्थिति बनती है। इससे इलाज के साथ जलभराव और फिसलन की परेशानी भी झेलनी पड़ती है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1.10 लाख रुपए के पनीर के लिए सैंपल लैब भेज

राजधानी की डेयरियों पर रातभर हुई छापामार कार्रवाई, 275 किलो संदिग्ध पनीर किया जब्त

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार देर रात से आज सुबह तक डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान चलाकर 275 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया। जब्त पनीर की अनुमानित कीमत करीब 1.10 लाख रुपये बताई गई है। अधिकारियों ने मौके से पनीर के नमूने लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप होने को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश के निर्देश पर हुई कार्रवाई में टीम ने देर रात जैन डेयरी कोलार और तड़के न्यू कृष्णा डेयरी, नादरा बस स्टैंड तथा नेशनल डेयरी का निरीक्षण किया। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे रेलवे स्टेशन, नादरा बस स्टैंड और आईएसबीटी सहित कई स्थानों पर भी जांच की गई। अधिकारियों को कुछ प्रतिष्ठानों पर पनीर की गुणवत्ता और स्वरूप को लेकर संदेह हुआ, जिसके बाद नियमानुसार पनीर जब्त कर सैंपल लिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि लैब रिपोर्ट आने से पहले जब्त पनीर को एनालॉग पनीर घोषित नहीं किया गया है। विभाग यह भी जांच रहा है कि कहीं वनस्पति वसा या किसी वैकल्पिक उत्पाद को पनीर के नाम पर तो नहीं बेचा जा रहा था। मानकों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई होगी। शहर में ई-कॉमर्स और संगठित रिटेल प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। डेटा कॉलोनी स्थित डी-मार्ट रेडी से दुग्ध उत्पादों के नमूने लिए गए। ब्लिंकइट, डी-मार्ट, फ्लिपकार्ट और रिलायंस मॉल पर भी जांच की जा रही है।

इन स्थानों पर चली कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार देर रात से आज सुबह तक शहर के अलग-अलग इलाकों में डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। जैन डेयरी कोलार के बाद न्यू कृष्णा डेयरी, नादरा बस स्टैंड और नेशनल डेयरी का निरीक्षण किया गया। सुबह करीब 4 बजे रेलवे स्टेशन, नादरा बस स्टैंड और आईएसबीटी समेत कई स्थानों पर भी खाद्य पदार्थों की जांच हुई। अधिकारियों को कुछ जगह पनीर की गुणवत्ता और स्वरूप पर संदेह हुआ। इसके बाद करीब 275 किलो पनीर जब्त कर लिया गया। विभाग ने मौके से विधिवत नमूने लिए और उन्हें खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिया। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही संबंधित उत्पाद की वास्तविक गुणवत्ता और मानकों के पालन की स्थिति स्पष्ट होगी।

रिपोर्ट से पहले 'एनालॉग पनीर' का ठप्पा नहीं

खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि जब्त किए गए पनीर को फिलहाल एनालॉग पनीर नहीं माना गया है। विभाग के अनुसार केवल स्वरूप या गुणवत्ता पर संदेह के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए प्रयोगशाला में उत्पाद की संरचना और गुणवत्ता की जांच जरूरी है। टीम यह भी पता लगा रही है कि कहीं वनस्पति वसा या किसी अन्य वैकल्पिक उत्पाद को पनीर के नाम पर तो नहीं बेचा जा रहा था। यदि लैब रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डी-मार्ट रेडी से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक विभाग कर रहा निगरानी

एनालॉग पनीर और वैकल्पिक दुग्ध उत्पादों की बिक्री पर निगरानी बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने संगठित रिटेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर भी रुख किया है। डेटा कॉलोनी स्थित डी-मार्ट रेडी का निरीक्षण कर पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों के नमूने लिए गए। टीम ने उत्पादों की गुणवत्ता के साथ लेबलिंग, पैकेजिंग, निर्माण और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की। विभाग ब्लिंकइट, डी-मार्ट, फ्लिपकार्ट और रिलायंस मॉल जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उत्पादों की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों का फोकस यह पता लगाने पर है कि कहीं एनालॉग या किसी वैकल्पिक उत्पाद को पनीर के नाम पर तो नहीं बेचा जा रहा। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

टीआईटी कॉलेज का मामला

नाम लेकर बुलाने से सीनियर ने चार जूनियरों पर किया चाकू से हमला

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी में मामूली विवादों ने हिंसक रूप ले लिया। टीआईटी कॉलेज के बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र कृष्णा साहू ने नाम लेकर बुलाने से नाराज होकर चार जूनियर छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। कृष्णा सोनागिरी स्थित फ्लैट में रहता है। सोमवार को उसके सहपाठी रितिक ने बाइक की चाबी द्वितीय वर्ष के छात्र दिव्यांश राजपूत को कृष्णा के पास पहुंचाने के लिए दी थी। दिव्यांश अपने साथियों पियूष पटेल, आयुष और विपुल के साथ फ्लैट पहुंचा। दरवाजा नहीं खुला तो छात्रों ने नाम लेकर आवाज लगाई। इससे नाराज कृष्णा ने विवाद किया और बाद में चाकू से हमला कर दिया। चारों घायल हुए। पुलिस ने कृष्णा को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

दूसरी घटना निशातपुरा क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई। पड़ोस की युवती से फोन पर बात करने से नाराज उसके भाइयों आशु और छोटू ने 24 वर्षीय रेहान मंसूरी पर चाकू से हमला कर दिया। पेट और उंगलियों में चोट लगने के बाद दोनों फरार हो गए। वहीं, छोला मंदिर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने 17 वर्षीय किशोर पर तलवार से हमला कर दिया। किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश कर रही है।

बाइक की चाबी पहुंचाने गए तो बिगड़ी गई बात

टीआईटी कॉलेज के चार जूनियर छात्र बाइक की चाबी देने कृष्णा साहू के सोनागिरी स्थित फ्लैट पहुंचे थे। दरवाजा खटखटाने के बाद भी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कृष्णा को नाम लेकर आवाज दी। आरोप है कि इससे वह नाराज हो गया और दरवाजा खोलकर छात्रों से विवाद करने लगा। कृष्णा ने कहा कि सीनियर को नाम लेकर क्यों बुलाया। छात्रों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ गया। इसके बाद कृष्णा कमरे के अंदर गया और चाकू लेकर बाहर आया। उसने दिव्यांश, पियूष, आयुष और विपुल पर हमला कर दिया। दिव्यांश के कंधे, पियूष और विपुल के हाथ तथा आयुष के पेट में चोट लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

भोपाल रेलवे स्टेशन पर गंदगी पड़ी भारी; एनजीटी के निर्देश पर 10.06 लाख रुपए का जुर्माना, वसूली का नोटिस जारी

भोपाल। दोपहर मेट्रो

भोपाल रेलवे स्टेशन पर कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में खामियां रेलवे पर भारी पड़ गईं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेलवे के खिलाफ 10.06 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन पेश किया है। सुनवाई में एनजीटी की पीठ ने बताया कि उक्त राशि की वसूली के लिए रेलवे को नोटिस जारी किया गया है।

सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई। इसमें पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों के आधार पर पर्यावरणीय क्षति का आकलन किए जाने की जानकारी दी गई। रेलवे ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर एनजीटी ने दो सप्ताह की मोहलत दी। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। संयुक्त समिति की निरीक्षण रिपोर्ट में स्टेशन पर कचरा प्रबंधन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई थी। प्लेटफार्म नंबर चार और पांच के पास नालियां चोक और ओवरफ्लो मिली थीं। प्लेटफार्म छह पर ठोस कचरा रखने का स्थान भी पूरी तरह ढंका नहीं था। रेलवे ट्रैक और आसपास कचरे से भरे बैग पाए गए।

रिपोर्ट में कचरे के आदर्श संग्रहण तथा गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था में भी कमियां बताई गईं। निरीक्षण के दौरान रेलवे ने नए कचरा भंडारण स्थल के निर्माण की जानकारी दी थी।

नालियां चोक, ट्रैक के पास मिले कचरे से भरे बैग

संयुक्त समिति की रिपोर्ट में भोपाल रेलवे स्टेशन पर सफाई और कचरा प्रबंधन की कई कमियां सामने आईं। प्लेटफार्म नंबर चार और पांच के पास नालियां चोक होने के साथ पानी ओवरफ्लो मिला। प्लेटफार्म छह पर ठोस कचरा भंडारण स्थल पूरी तरह ढंका नहीं था। रेलवे ट्रैक और आसपास कचरे से भरे बैग भी पाए गए। निरीक्षण में गीले और सूखे कचरे को अलग रखने की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। रिपोर्ट के बाद पर्यावरणीय क्षति का आकलन किया गया और 10.06 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि तय की गई। रेलवे ने नए कचरा भंडारण स्थल के निर्माण की जानकारी भी समिति को दी थी।

कोलार थाना क्षेत्र के नेताजी हिल्स का मामला

छत से पानी निकालते समय हाइटेंशन लाइन की चपेट में आए NHDC के सीनियर मैनेजर, मौत

भोपाल। दोपहर मेट्रो

कोलार थाना क्षेत्र के नेताजी हिल्स में सोमवार सुबह बारिश के बाद छत पर जमा पानी निकालना एनएचडीसी के वरिष्ठ प्रबंधक के लिए जानलेवा साबित हुआ। लोहे की रॉड हाईटेंशन लाइन से छू जाने के कारण करंट की चपेट में आए जयप्रकाश कटियार (52) की मौत हो गई। वह श्यामला हिल्स स्थित नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएचडीसी) के मुख्यालय में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

पुलिस के अनुसार तेज बारिश से जयप्रकाश के मकान की छत पर काफी पानी जमा हो गया था। रात में भी परिवार के सदस्य पानी निकालने में जुटे थे। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे जयप्रकाश दोबारा छत पर जमा पानी साफ करने पहुंचे। वह लोहे की रॉड से पानी की निकासी का रास्ता बना रहे थे। इसी दौरान रॉड पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से संपर्क में आ गई। लाइन के संपर्क में आते ही तेज धमाका हुआ और जयप्रकाश को करंट का जोरदार झटका लगा। वह अचेत होकर छत पर गिर पड़े। धमाके की आवाज सुनकर स्वजन तुरंत छत पर पहुंचे और उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोलार थाने के एसआई जोगेंद्र नैगी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया।

मेट्रो एंकर | राजा भोज एयरपोर्ट को e-Visa एंट्री प्वाइंट का दर्जा, सांची-भीमबेटका पर्यटन को लगेंगे पंख

अब दिल्ली-मुंबई के बजाय सीधे भोपाल पहुंच सकेंगे विदेशी यात्री

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी भोपाल की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को नई उड़ान मिलने जा रही है। भारत सरकार ने ई-वीजा सुविधा के तहत देश में 11 नए प्रवेश बिंदु जोड़े हैं, जिनमें भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी शामिल है। अब ई-वीजा के पात्र विदेशी यात्री भोपाल से सीधे भारत में प्रवेश कर सकेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश आने वाले विदेशी यात्रियों को अक्सर दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में उतरकर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी।

नई व्यवस्था के बाद देश में ई-वीजा से प्रवेश के कुल 88 अधिकृत बिंदु हो गए हैं। इनमें 37 एयरपोर्ट, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 लैंड पोर्ट शामिल हैं। वर्तमान में 172 देशों के नागरिक ई-वीजा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भोपाल को ई-वीजा एंट्री प्वाइंट बनाए जाने का सबसे बड़ा फायदा पर्यटन क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। राजधानी के आसपास सांची और भीमबेटका जैसे विश्व प्रसिद्ध विरासत स्थल हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए सीधे भोपाल पहुंचना आसान होने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों, कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए भी भोपाल पहुंचना आसान होगा। विदेशी यात्रियों की संख्या बढ़ने से होटल, टैक्सी, टूर गाइड और हस्तशिल्प कारोबार को भी लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, राजा भोज एयरपोर्ट के ई-वीजा एंट्री प्वाइंट बनने से भोपाल और आसपास के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा मिलने की उम्मीद है। सांची और भीमबेटका आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए यात्रा आसान होगी। इसके अलावा विदेशी निवेशक, कारोबारी प्रतिनिधिमंडल और विशेषज्ञ सीधे भोपाल पहुंच सकेंगे। इससे होटल, टैक्सी, टूर गाइड और स्थानीय हस्तशिल्प कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। विदेशों में रहने वाले मध्य प्रदेश से जुड़े लोग भी अपने विदेशी मित्रों और रिश्तेदारों को सीधे भोपाल बुला सकेंगे।

88 जगहों से अब ई-वीजा के जरिए एंट्री

ई-वीजा नेटवर्क के विस्तार के बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक वीजा के जरिए प्रवेश करने वाले अधिकृत बिंदुओं की संख्या 88 हो गई है। इनमें 37 एयरपोर्ट, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 लैंड पोर्ट शामिल हैं। नए 11 प्रवेश बिंदुओं में भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के साथ आंध्र प्रदेश का तिरुपति एयरपोर्ट और कई लैंड पोर्ट भी शामिल किए गए हैं। वर्तमान में 172 देशों के नागरिक भारत की ई-वीजा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इससे विदेशी यात्रियों को भारत पहुंचने के लिए पारंपरिक वीजा प्रक्रिया की तुलना में अधिक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। हालांकि यात्रियों को यात्रा से पहले आधिकारिक ई-वीजा पोर्टल पर प्रवेश बिंदुओं की सूची और अपने वीजा की पात्रता जरूर जांचनी होगी।

'विभाजन विभीषिका' दिवस पर सिंधी नाटक 'वारीअ संदो कोटु' का मंचन आज

भोपाल। दोपहर मेट्रो

'विभाजन विभीषिका दिवस' की पूर्व संध्या पर भोपाल में आज शाम 6.30 बजे नंदवानी भवन, संत हिरदाराम नगर में सिंधी नाटक वारीअ संदो कोटु 'रेत का किला' का मंचन किया जा रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद ,नई दिल्ली की ओर से सिंधु दर्पण नाट्य संस्था यह नाटक निर्देशक कविता इसरानी के निर्देशन में कर रही है। यह नाटक साहित्य अकादमी सम्मानित लेखक लखमी खिलानी की अमर रचना है। वे 90 वर्ष के हैं और इन दिनों बैंगलोर में निवास कर रहे हैं। नाटक में बताया गया है कि15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ। तिरंगा लहराया गया। जश्न मनाया परंतु 14 अगस्त, 1947 की रात भारत देश के विभाजन के साथ दिलों का भी बंटवारा हो गया। विभाजन की विभीषिका से सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ तो वह सिंधी समाज था। सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले समाज बंधुओं को धर्म रक्षा की खातिर अपनी जमीन, अपने मकान, अपना व्यापार सब कुछ छोड़कर एक अनजानी सी मंजिल की ओर रवाना होना पड़ गया। नाटक में युवाओं द्वारा आधुनिक जीवन शैली अपनाने और पारंपरिक मूल्यों की उपेक्षा के बारे में भी एक सार्थक संदेश दिया गया है।

कृषक कल्याण वर्ष-2026 | प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक व डिजिटल गवर्नेंस पर फोकस के साथ कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार

कृषि के लिए ₹1.15 लाख करोड़ का प्लान, 15 विभाग मिलकर बदलेंगे खेती की तस्वीर

भोपाल

कृषि और किसान कल्याण मध्यप्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को अधिकारिक तौर पर 'कृषक कल्याण वर्ष' घोषित किया है। इस विशेष वर्ष के नीतिगत संकल्पों को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने कृषि और उससे जुड़े संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कृषि को लेकर उस समग्र दृष्टिकोण और दूरदर्शी सोच को समर्पित है, जिसमें वे पारंपरिक खेती के आधुनिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय दोगुनी करने पर विशेष बल देते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहते हैं, "देश में अन्न, फल, सब्जी, मसाले, दूध व फूल उत्पादन में बेजोड़ पहचान रखने वाला हमारा प्रदेश अब नई सोच के साथ इस क्षेत्र में और मजबूत हो, इसके लिए राज्य सरकार कई मजबूत कदम उठा रही है।"

अब एक मंच पर 15 विभाग

कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव के लिए प्रदेश के 15 प्रमुख विभागों को एक ही मंच पर लाया गया है। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य विकास, सहकारिता, जल संसाधन, राजस्व और ऊर्जा विभाग शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि योजनाएं अब फाइलों में नहीं अटकती, बल्कि तेज गति से पूरी होती हैं।

तकनीक और इनोवेशन पर जोर

इस पूरे अभियान का फोकस बड़े किसानों के साथ ही छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक व सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके जरिए छोटी जोत वाले किसानों की आधुनिक ड्रोन जैसी तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। गेहूं उपार्जन में रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान फसल विविधीकरण पर केंद्रित है।

किसानों के लिए 3 बड़े फायदे

1. **दोहरी आय के साधन:** पारंपरिक फसलों के साथ फल, सब्जी, दूध व मछली पालन को विशेष बढ़ावा मिलने से किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता खुला है।
2. **लागत में भारी कमी:** हर ब्लॉक में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर बनने से खाद का खर्च होगा शून्य
3. **विवादमुक्त भू-अधिकार:** डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कृषि निवेश को सीधा प्रोत्साहन

अन्नदाता का सम्मान... बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट की बैठक में ₹27,500 करोड़ की सौगातें

फसल ऋण चुकाने के लिए 12 महीने, 0% ब्याज जारी; जमीन अधिग्रहण पर अब 4 गुना मुआवजा

भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार ने 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' के नीतिगत फैसलों को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नीतियों को सीधे किसानों के खेतों और गांवों के बीच जाकर उनके अनुरूप बनाने के लिए बड़वानी में प्रदेश की पहली ऐतिहासिक कृषि कैबिनेट आयोजित की गई। बैठक में किसानों के हित कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा भी की गई। इसके तहत छोटे किसानों को अब फसल ऋण चुकाने के लिए पूरे 12 महीने मिलेंगे। इसके साथ ही 0% ब्याज और जमीन अधिग्रहण में बाजार दर पर 4 गुना मुआवजा जैसे अहम कदम कृषि क्षेत्र की सूरत बदलने वाले साबित होंगे। बैठक में सूबे के संपूर्ण कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। इसके तहत कृषि के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और सिंचाई नेटवर्क के तीव्र विस्तार के लिए ₹27,500 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जो राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है।

बड़वानी में हुई पहली कृषि कैबिनेट में सीएम डॉ. मोहन यादव व मंत्रीगण।

कर्ज के दबाव से मुक्ति, सही समय पर सही दाम में बेचिए अपनी उपज

छोटे किसानों को बड़ा फायदा: अब औने-पौने दाम पर फसल बेचने के दबाव खत्म
ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर के साथ वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू की गई है। इससे छोटे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें ऋण लेने की तिथि से उसका भुगतान करने के लिए पूरे 12 महीने का पर्याप्त समय मिलेगा। इस व्यवस्था से किसानों पर फसल कटते ही औने-पौने दाम में उपज बेचकर कर्ज चुकाने का मानसिक दबाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वे सही समय पर सही दाम में उपज बेच सकेंगे।

लागत पर मुनाफा: कंबाइन हार्वेस्टर्स को टोल से राहत
कृषि कार्यों में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को गहराई से समझते हुए सरकार ने कंबाइन हार्वेस्टरों को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के सभी टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रहण से पूर्णतः छूट दे दी है, जिससे हार्वेस्टर संचालकों और किसानों की लागत घटेगी।

सामाजिक सुरक्षा पर फोकस: कृषि यंत्रीकरण के 2800 करोड़ से ज्यादा
कपास उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए खंडवा और बुरहानपुर की मंडियों में मंडी शुल्क को 1 रुपये से घटाकर मात्र 55 पैसे प्रति सौ रुपये करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि यंत्रीकरण को नई गति देने के लिए आगामी 5 वर्षों हेतु 2,868 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो साबित करती है कि सरकार का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि अन्नदाता की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

किसान हित में 5 बड़े फैसले

1. रबी व खरीफ में खाद की पर्याप्त उपलब्धता और फसल बीमा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट मंत्रियों की उच्च स्तरीय विशेष समिति गठित।
2. प्राइस सपोर्ट स्कीम के सुरक्षा कवच से प्रदेश के 91 हजार से अधिक किसानों से 2.71 लाख मीट्रिक टन चने की रिकॉर्ड खरीदी पूरी।
3. मूल्य समर्थन के तहत 76 हजार 500 से अधिक किसानों से 1.85 लाख मीट्रिक टन मसूर का सफल उपार्जन कर सीधा आर्थिक लाभ दिया गया।
4. समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी के साथ ही ₹ 600 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त बोनस पर उड़द का शत-प्रतिशत उपार्जन सुनिश्चित।
5. 10.76 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने के साथ ब्लॉक स्तर पर 265 नई मिट्टी परीक्षण लैब्स शुरू।

पारदर्शिता की नई मिसाल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत खातों में बिना कटौती के सीधे पहुंच रही आर्थिक सहायता

डीबीटी से 84 लाख किसानों के खातों में पहुंचे ₹53 हजार करोड़

भोपाल

मध्यप्रदेश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे बैंक खातों में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन स्तर को पूरी तरह से बदल दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा डिजिटल गवर्नेंस नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश के 84 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में अब तक ₹53,076 करोड़ की विशाल और ऐतिहासिक राशि सफलतापूर्वक अंतरित की जा चुकी है, जिससे बिचौलियों और कमीशनखोरी की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। आधिकारिक बजटीय और विभागीय आंकड़ों के अनुसार, योजना के प्रारंभ वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के 84 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों के खातों में ₹32,198 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। इसी के समांतर कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत भी 84 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में अब तक की 14 किस्तों में कुल ₹20,878 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया जा चुका है। इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलू यह है कि खरीफ और रबी सीजन की बुआई के ठीक पहले यह वित्तीय सहायता बिना किसी प्रशासनिक विसंगति के सीधे किसानों के पास पहुंचती है।

इससे किसानों को उन्नत बीज, जैविक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए किसी स्थानीय ऋणदाता के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पारदर्शिता की यह अनूठी प्रणाली आज पूरे देश में डिजिटल गवर्नेंस का सबसे बड़ा और सफल उदाहरण बनकर उभरी है।

58 लाख से अधिक डिजिटल फार्मर आईडी तैयार

फार्मर रजिस्ट्री के मामले अब मध्य प्रदेश देश में नंबर एक

भोपाल

मध्यप्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित विशेष कैंपों और आधुनिक सर्वे तकनीक के उपयोग के साथ अब तक 58 लाख से अधिक किसानों की विशिष्ट और प्रमाणित फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 68 लाख 11 हजार संपत्ति अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। योजना का 98% कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। डिजिटल भू-अभिलेख की इस अनूठी पहल से भूमि संबंधी आपसी विवादों

68.11 लाख संपत्ति अधिकार अभिलेख भी तैयार किए जा चुके

में भारी कमी आएगी, कृषि निवेश को भारी प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों को प्रमाणित भू-अधिकार उपलब्ध होने से बैंक से लोन लेने में किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

'विंड्स' कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म स्तर पर होगी वर्षा की सटीक मैपिंग

हर ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाएंगे स्वचालित रेनगेज, तहसील स्तर पर होंगे आटोमैटिक वेदर स्टेशन

भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश में पहली बार मौसम निगरानी का सबसे हाइटेक मॉडल लागू करने जा रही है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रेनगेज और प्रत्येक तहसील स्तर पर अत्याधुनिक आटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। क्रांतिकारी विंड्स कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो रही इस नई तकनीकी व्यवस्था से न केवल मौसम की सटीक और तात्कालिक भविष्यवाणी संभव होगी, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर वर्षा की प्रामाणिक मैपिंग भी की जा सकेगी। इससे किसानों को कब बोवनी करनी है, कब सिंचाई करनी है और कब कटाई करनी है, आदि बातों के सटीक पूर्वानुमान से सही समय निर्धारित करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले अन्नदाताओं के लिए राहत एवं मुआवजा वितरण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मानवीय बनाया है। पिछले ढाई वर्षों के कार्यकाल के दौरान विभिन्न आपदाओं से प्रभावित हुए 24 लाख 14 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹2,106 करोड़ से अधिक की राहत व मुआवजा राशि का सीधा और त्वरित अंतरण किया गया है।

किसानों को मिलने वाले मुख्य लाभ

त्वरित क्लेम निपटारा: हर ग्राम पंचायत में रेनगेज लगाने से नुकसान का सटीक आकलन होगा और दावों में होने वाली देरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।

मौसम का एडवांस अलर्ट: तहसील स्तर पर स्वचालित वेदर स्टेशन से आंधी, तूफान, भारी बारिश की सटीक चेतावनी किसानों को समय पर मिलेगी।

सीधे खाते में भुगतान: आपदा राहत व फसल बीमा की स्वीकृत राशि बिना किसी कमीशन या विसंगति के सीधे हितग्राही के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

कृषक कल्याण वर्ष 2026

10 मुख्य नीतिगत आयाम

किसानों की आय बढ़ाने से लेकर एआई आधारित खेती और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने की रणनीति... कृषक कल्याण वर्ष-2026 के लिए प्रदेश सरकार ने 10 बड़े नीतिगत आयाम तय किए हैं। फोकस है खेती को लाभ का कारोबार बनाने के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाना...

1. **आधुनिक कृषि और फसल विविधीकरण** पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा।
2. **आय में वृद्धि और मूल्य स्थिरीकरण** उपज का सही दाम और बाजार के उतार-चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा।
3. **प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार** हर ब्लॉक में जैविक खेती के विशेष क्लस्टर्स का निर्माण।
4. **जल और मृदा संरक्षण** सिंचाई परियोजनाओं का तीव्र विस्तार और उन्नत जल प्रबंधन।
5. **कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन** पराली और वेस्ट से सीएनजी व बायोगैस का निर्माण।
6. **मंडियों का आधुनिकीकरण** प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को ई-नाम और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना।
7. **वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग** जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तैयार करना।
8. **अनुसंधान और नवाचार** एआई, ड्रोन और स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों का प्रयोगशाला से खेत तक हस्तांतरण।
9. **कृषि पर्यटन को बढ़ावा** ग्रामीण संस्कृति और कृषि लोकरंग के माध्यम से आय के नए साधन।
10. **डिजिटल गवर्नेंस** फार्मर रजिस्ट्री और 100% पारदर्शी व्यवस्था को धरातल पर लागू करना।

बाय इन्विटेशन... गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की जुबानी जानें प्राकृतिक खेती के सारे वैज्ञानिक राज

कैंसर, बीपी, डायबिटीज से जैसी घातक बीमारियों से बचना है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी, यही धरती मां को जहर मुक्त बनाएगी: आचार्य देवव्रत

आचार्य देवव्रत
गुजरात के राज्यपाल

जब मैं कुरुक्षेत्र गुरुकुल की 180 एकड़ भूमि पर रासायनिक खाद डालता था, तो मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। केंचुए गायब थे और पैदावार लगातार गिर रही थी। तब मैंने एक फैसला किया- धरती मां को यूरिया और डीएपी के जानलेवा जहर से मुक्त करने का। आज मैं अपने उसी सफल अनुभव से आपको बताने आया हूं कि यूरिया और कीटनाशक डालकर हम खेतों में अन्न नहीं, बल्कि धीमा जहर उगा रहे हैं। क्या आपने कभी पंजाब से बीकानेर जाने वाली उस 'कैंसर ट्रेन' के बारे में सुना है? वह ट्रेन कोई साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि खेतों में अंधाधुंध डाले गए रसायनों का खौफनाक सच है, जो हर रोज मासूम जिंदगियों को कैंसर के जरिए मौत के मुंह में धकेल रही है।

प्राकृतिक खेती कोई पुराना ढर्रा या पिछड़ी हुई पद्धति नहीं है। यह एक परम और शुद्ध विज्ञान है जो आने वाली नस्लों को नया जीवन दे सकता है। अक्सर हमारे किसान भाई एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। वे जैविक और प्राकृतिक खेती को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। श्रीलंका की बर्बादी का कारण उसका अधूरा और गलत जैविक मॉडल था। जैविक खेती बेहद खर्चीली है। आम किसान इसका खर्च नहीं उठा सकता।

मध्यप्रदेश सरकार भी कर रही है प्राकृतिक खेती को

- प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को प्रति गाय ₹900 प्रति माह की सहायता।
- जीवामृत तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण व ड्रम खरीदने हेतु ₹7,500 की मदद।
- पारदर्शिता और सीधे लाभ के लिए मप्र प्राकृतिक खेती पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन।
- सभी 313 विकासखंडों में विशेष क्लस्टर बनाकर किसानों को निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मंडियों में विशेष काउंटर व डिजिटल प्लेटफॉर्म।

एक देसी गाय का गोबर और गोमूत्र ही है असली ताकत: इसके विपरीत, मेरी प्राकृतिक खेती पूरी तरह शून्य लागत पर आधारित है। इसमें बाजार से एक ढेला भी नहीं खरीदना पड़ता। एक देसी गाय के मात्र 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा मित्र जीवाणु होते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जब हम गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ को मिलाकर जीवामृत तैयार करते हैं और उसे खेतों में डालते हैं, तो मिट्टी में सोए हुए करोड़ों केंचुए जाग जाते हैं। वे जमीन में नीचे से ऊपर तक आवाजाही करके मिट्टी को बिना ट्रैक्टर चलाए खुद-ब-खुद पोला (नरम) और उपजाऊ बना देते हैं। इससे फसलों की पैदावार तो बढ़ती ही है, साथ ही मल्चिंग (आच्छादन) के कारण खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई में आधा पानी खर्च होता है। यह खेती पर्यावरण को बचाती है और इंसानों को कैंसर, डायबिटीज व बीपी जैसी भयानक बीमारियों से दूर रखती है।

"राजनीति से रिटायरमेंट के बाद मैं स्वयं प्राकृतिक खेती करूंगा। यह आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का पवित्र ईश्वरीय कार्य है।" - **श्री अमित शाह,** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

D-11076/26

समुद्र का बढ़ता तापमान

जलवायु संकट की आहट अब केवल तपती सड़कों और पिघलते ग्लेशियरों से नहीं सुनी जा सकती। पृथ्वी का वह विशाल हिस्सा, जिसे हम समुद्र कहते हैं, भी लगातार गर्म हो रहा है। जुलाई में वैश्विक समुद्री सतह का तापमान इस महीने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना महज मौसम का एक आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज का गंभीर संकेत है। समुद्र की सतह पर दर्ज यह गर्मी आने वाले दिनों में धरती के मौसम, खेती और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी सेवा कॉपरनिकस का आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महासागर पृथ्वी की अतिरिक्त गर्मी का सबसे बड़ा भंडार बन चुके हैं। वैज्ञानिक आकलन बताते हैं कि मानवीय गतिविधियों से पैदा अतिरिक्त ऊष्मा का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्र सोख रहे हैं। यानी जो गर्मी हमें हवा में पूरी तरह महसूस नहीं होती, उसका बड़ा हिस्सा समुद्र अपने भीतर जमा कर रहे हैं। समस्या यह है कि समुद्र जितना गर्म होगा, उसका असर उतना ही लंबे समय तक बना रहेगा। इस चिंता के बीच भूमध्यरेखीय प्रशांत में अल-नीनो की तीव्रता बढ़ने की खबर स्थिति को और गंभीर बनाती है। अल-नीनो केवल प्रशांत महासागर की घटना नहीं है। इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में वर्षा, सूखा, तापमान और तूफानों के स्वरूप पर पड़ सकता है। यदि पहले से गर्म समुद्र के ऊपर ऐसी जलवायु घटना मजबूत होती है, तो मौसम की अनिश्चितता और चरम घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। समुद्र का बढ़ता तापमान सबसे पहले समुद्री जीवन को प्रभावित करता है। प्रवाल भित्तियों का क्षरण, समुद्री जीवों के आवास में बदलाव और जैव विविधता पर बढ़ता दबाव आने वाले समय की बड़ी चुनौती हो सकते हैं। इसका असर समुद्र से रोजी-रोटी कमाने वाले मछुआरों और तटीय समुदायों पर भी पड़ेगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने पर आर्थिक नुकसान भी उससे अलग नहीं रह सकता। गर्म समुद्र का अर्थ अधिक वाष्पीकरण और वातावरण में अधिक नमी भी है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर यही अतिरिक्त ऊर्जा शक्तिशाली तूफानों को जन्म देने या उन्हें अधिक तीव्र करने में भूमिका निभा सकती है। वहीं दूसरी ओर अल-नीनो कुछ क्षेत्रों में वर्षा घटाकर सूखे की मार बढ़ा सकता है। एक ही जलवायु परिवर्तन कहीं बाढ़ और कहीं सूखे का खतरा पैदा कर सकता है।

विश्व अंगदान दिवस

अंगदान की संस्कृति से किसी का जीवन बनकर दे सकतें है मानवता को नई दिशा

ललित गर्ग
स्तंभकार

मनुष्य जीवनभर अपने लिए बहुत कुछ अर्जित करता है-धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, संबंध और सुविधाएँ। लेकिन जीवन की अंतिम घड़ी में इन सबका महत्व समाप्त हो जाता है। तब यदि हमारे शरीर का कोई अंग किसी दूसरे मनुष्य की धड़कन बन जाए, हमारी आँखें किसी अंधेरे जीवन में रोशनी भर दें, हमारा यकृत या गुर्दा किसी परिवार के बुझते चिराग को फिर से जला दे, तो इससे बड़ी जीवन-सार्थकता और क्या हो सकती है? अंगदान मृत्यु के बाद भी जीवन को जारी रखने की वह मानवीय संभावना है, जो मनुष्य को केवल अपने लिए जीने वाले प्राणी से उठाकर मानवता के लिए जीने वाला बना देती है। विश्व अंगदान दिवस हमें इसी महान विचार से जोड़ता है। आज आवश्यकता केवल अंगदान के बारे में जानकारी देने की नहीं, बल्कि हमारी सोच बदलने की है। हमें यह प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि जिस शरीर को मृत्यु के बाद पंचतत्व में विलीन होना है, उसके उपयोगी अंग यदि किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं तो उन्हें अपने साथ मिट्टी में मिला देना अधिक सार्थक है या किसी की सांसों का हिस्सा बना देना? मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन का कारण बनना हमारे हाथ में है।

भारत की सांस्कृतिक स्मृति में शरीर और जीवन के महान त्याग की परंपरा बहुत पुरानी है। महर्षि दधीचि की कथा इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। पौराणिक परंपरा के अनुसार जब देवताओं को असुरों से संघर्ष के लिए ऐसे अस्त्र की आवश्यकता हुई जिसे दधीचि की अस्थियों से बनाया जा सके, तब महर्षि दधीचि ने लोककल्याण के लिए अपना शरीर ही त्याग दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और उससे जनकल्याण की रक्षा हुई। यह कथा आधुनिक अर्थों में अंगदान की चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अपने शरीर को भी समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर देने की भारतीय त्याग-चेतना का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक अवश्य है। भारत के राष्ट्रपति सचिवालय ने भी अंग एवं देहदान की भारतीय परंपरा को समझाते हुए महर्षि दधीचि के इस प्रसंग का उल्लेख किया है। हमारी परंपरा में राजा शिवि की कथा भी त्याग और जीव-दया की अद्भुत मिसाल है। एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस तक देने की तत्परता दिखाई। चाहे ये प्रसंग धार्मिक आख्यान हों, लेकिन इनके भीतर छिपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है-अपने जीवन और शरीर को केवल अपनी निजी संपत्ति न समझना, बल्कि उसे व्यापक जीवन के कल्याण से जोड़ना। जैन दर्शन का सूत्र 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' भी यही बताता है कि जीव एक-दूसरे के उपकार के लिए हैं। अंगदान इस विचार का आधुनिक वैज्ञानिक रूप कहा जा सकता है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इस मानवीय भावना को वास्तविक जीवन बचाने की शक्ति प्रदान कर दी है। वर्ष 1954 में दुनिया का पहला सफल मानव किडनी प्रत्यारोपण हुआ। रोनाल्ड ली हेरिक ने अपनी एक किडनी अपने जुड़वां भाई रिचर्ड को दान की थी। यह घटना चिकित्सा इतिहास में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत बनी, जिसने आगे चलकर अंग प्रत्यारोपण को लाखों लोगों के लिए जीवन की आशा बना दिया। इसके बाद 1967 में मानव हृदय प्रत्यारोपण की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि चिकित्सा विज्ञान मनुष्य की मृत्यु और जीवन के बीच खड़ी कई दीवारों को तोड़ सकता है। भारत ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय यात्रा की है। देश में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण 1 दिसंबर 1971 को चेन्नई के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर में हुआ था। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन भारत में हजारों लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण जीवन का नया द्वार बनेगा। आज चिकित्सा तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किडनी, लिवर, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और आंत जैसे अंगों के साथ कॉर्निया, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व जैसे ऊतकों का भी प्रत्यारोपण संभव है।

लेकिन विज्ञान की क्षमता जितनी बढ़ी है, हमारी सामाजिक चेतना उस गति से नहीं बढ़ पाई। यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में आज भी प्रत्यारोपण की आवश्यकता और उपलब्ध अंगों के बीच बड़ा अंतर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024 में देश में अंग प्रत्यारोपण की गतिविधि व्यापक रही, लेकिन मृतक दाताओं की संख्या अभी भी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ साफ है-हमारे अस्पतालों में तकनीक है, डॉक्टर हैं, सर्जरी की क्षमता है, लेकिन जीवन बचाने के लिए पर्याप्त अंग नहीं हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें अंगदान को मृत्यु की चर्चा नहीं, जीवन की चर्चा बनाना होगा। परिवारों में इस विषय पर समय रहते बातचीत होनी चाहिए। स्कूलों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया को मिलकर ऐसी वातावरण-निर्मिति करनी होगी जिसमें अंगदान सुनते ही भय नहीं, बल्कि करुणा और जीवन बचाने का भाव पैदा हो।

इस विश्व अंगदान दिवस पर हमें केवल यह संकल्प नहीं लेना चाहिए कि 'अंगदान करेंगे', बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर यह संकल्प लेना चाहिए कि अंगदान के बारे में अपने परिवार से बात करेंगे, भ्रम दूर करेंगे और समाज में जीवन बचाने वाली इस चेतना को फैलाएँगे। क्योंकि जीवन का अंतिम अध्याय मृत्यु नहीं होना चाहिए। वह किसी दूसरे के जीवन की नई शुरुआत भी बन सकता है। आइए अपने जीवन की अंतिम विरासत मानवता के नाम करें। अंगदान का दीप जलाएँ, ताकि किसी की बुझती जिंदगी में उजाला हो। अपनी मृत्यु को किसी दूसरे की जिंदगी का कारण बनाएँ-क्योंकि इससे सुंदर मृत्यु और इससे सार्थक जीवन शायद ही कोई हो।

'शरीर चला जाए, पर उसकी करुणा जीवित रहे।
सांसें रुक जाएं, पर किसी और की सांसें चलती रहें।
यही अंगदान है, यही मानवता का महादान है।'

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

सिगरेट- शराब- तंबाकू की तरह सोशल मीडिया पर भी लगे वैधानिक चेतावनी?

किशन सनमुखदास भावनानीं
स्तंभकार

सोशल मीडिया का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, नींद और जीवन- शैली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है इसलिए इसका सावधानी से उपयोग जरूरी है। डिजिटल युग में माता-पिता की जिम्मेदारी के साथ-साथ प्लेटफॉर्म डिजाइनर,टेक कंपनी, नियामक और सरकार सभी की जवाबदेही आवश्यक है। वैश्विक स्तरपर आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का केवल संचार माध्यम नहीं रह गया है।फेसबुक, इंस्टाग्राम व्हाट्सऐप,यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म अबसूचना मनोरंजन, कारोबार, शिक्षा, राजनीति और सामाजिक संपर्क की हमारी रोजमर्रा की व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इसी सुविधा के साथ गंभीर प्रश्न तेजी से सामने आ रहा है क्या सोशल मीडिया का अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय बन चुका है? जिस तरह कभी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और शराब को केवल व्यक्ति की निजी पसंद कहा जाता था,लेकिनसमय के साथ यह स्वीकार किया गया कि इनके दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते,उसी प्रकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिजाइन, एल्गोरिदम और हानिकारक कंटेंट को लेकर कंपनियों की जवाबदेही का सवाल उठ रहा है। विशेषकर बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत में बढ़ती कानूनी एवं नियामकीय सक्रियता संकेत दे रही है कि डिजिटल दुनिया में भी व्यक्तिगत पसंद' से 'कॉरपोरेट जवाबदेही' की यात्रा शुरू हो चुकी है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि सोशल मीडिया पर भी सिगरेट जैसी वैधानिक चेतावनी जरूरी है? इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जाना चाहिए कि अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है'? मेरे विचार से इस विचार को पूरी तरह खारिज करने के बजाय इसे आधुनिकडिजिटल सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए।लेकिन केवल चेतावनी लिख देना पर्याप्त नहीं होगा। जिस तरह तंबाकू पर चेतावनी के साथ एडवरटाइजिंग रेस्ट्रिक्टओन्स ,ऐज रेस्ट्रिक्टओन्स और पैकेजग रूल्स बनाए गए,उसी प्रकार सोशल मीडिया के लिए भी बहुस्तरीय व्यवस्था चाहिए।पहला कदम हो सकता है, नाबालिगों के लिए स्पष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा चेतावनी। दूसरा उम्र सत्यापन और चाइल्ड-सेफ डिफाल्ट सेटिंग्स । तीसरा, रात के समय पुश नोटिफिकेशन्स और एडिक्टिव इंगेजमेंट फीचर्स पर नियंत्रण। चौथा,बच्चों के लिए पर्सनालिज्ड रेकमेंडेशन सिस्टमस की स्वतंत्र ऑडिट । पांचवां,सीएसएएम , डीपफेक और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन सामग्री के खिलाफ अत्यंत तेज डिटेक्शन और रिमूवल व्यवस्था। छठा,कंपनियों की आंतरिक रिस्क रिपोर्ट्स और अलगोरिथमिक सेफ्टी असेसमेंट्स की स्वतंत्र निगरानी। और सातवां उल्लंघन होने पर ऐसा आर्थिक दंड जो कंपनी के लिए केवल 'व्यावसायिक खर्च बनकर न रह जाए।

न्यू मैक्सिको का ऐतिहासिक फैसला: 942 मिलियन डॉलर (लगभग 9000 करोड़) की कानूनी चोट और पब्लिक न्यूसेंस का सवाल इस बहस को सबसे बड़ा कानूनी आधार अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में 6 अगस्त 2026 को देखने को मिला। जहां जूरी ने मेटा प्लेटफार्मस को बच्चों को नुकसान पहुंचाने और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करने के मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए,इस मामले के दूसरे चरण में जज ब्रायन बिएडशीड ने मेटा को अतिरिक्त 567 मिलियन डॉलर देने का आदेश दिया। इससे दोनों चरणों की राशि मिलाकर कुल कानूनी देनदारी 942 मिलियन डॉलर हो गई। इस दूसरी राशि में से लगभग 420 डॉलर मिलियन युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं, जबकि शेष धनराशि जागरूकता, रोकथाम स्क्रीनिंग और संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च होगी। इसके पहले 24 मार्च 2026 को न्यू मैक्सिको की जूरी ने मेटा प्लेटफार्मस को बच्चों को नुकसान पहुंचाने और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करने के मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए 375 मिलियन डॉलर का सिविल पेनल्टी लगाया। न्यू मैक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे किसी बड़े टेक प्लेटफॉर्म के खिलाफ राज्य द्वारा ट्रायल में हासिल की गई ऐतिहासिक जीत बताया।

साथियों, इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात केवल जुर्माने की राशि नहीं है, बल्कि अदालत द्वारा प्लेटफॉर्म के सामाजिक प्रभाव को देखने का नजरिया है। जज ने मेटा को पब्लिक नूईसन्स के रूप में जिम्मेदार ठहराया और प्लेटफॉर्म के डिजाइन तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर कठोर रुख अपनाया। अदालत ने नाबालिगों के लिए नोटिफिकेशन, उम्र सत्यापन, स्क्रीन-टाइम और अन्य डिजाइन फीचर्स में बदलाव जैसे उपायों का आदेश दिया।

चेतावनी लिखें, उम्र सत्यापित करें या डिजाइन ही बदलें? इसको समझने की करें तो भारत में इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहां सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, समाचार, राजनीतिक संवाद और सामाजिक संपर्क तक इसकी पहुंच है। इसलिए अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह सीधा प्रतिबंध भारत में लागू करना एक जटिल प्रश्न होगा। भारत के लिए शायद अधिक व्यावहारिक रास्ता प्रतिबंध से पहले जवाबदेही का हो सकता है। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विशेष सुरक्षा देता है। इसके साथ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंटरमीडिएरी रूल्स प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारियों का आधार बनते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए ऐजअसन्शुरन्स पेरेंटल कण्ट्रोलस , प्राइवेसी- बाई - डिफाल्ट ,हरमफुल- कंटेंट डिटेक्शन और तेज शिकायत निवारण को और मजबूत किया जा सकता है।लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना होगा सेफ हर्बर का मतलब यह नहीं कि प्लेटफॉर्म हर कंटेंट के लिए स्वतः दोषी है,और केवल किसी एक विवाद से सेफ हर्बर अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। भारत में इंटरमीडिएरी प्रोटेक्शन विशिष्ट वैधानिक शर्तों और ड्यू डिलीजेंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई भी कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए।इसी प्रकार अमेरिका का सीओपीपीए मुख्य रूप से बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी और व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह से संबंधित है; इसे सोशल मीडिया एडिक्शन के लिए कोई सार्वभौमिक 'प्रतिबंध कानून' समझना सही नहीं होगा। यूरोपीय संघ का डीएसए इससे कहीं व्यापक प्लेटफार्म - रिस्क फ्रेमवर्क प्रदान करता है। वहां बच्चों को बेहेवियरल एडवरटाइजिंग से बचाने और प्लेटफार्म रिस्क्स का आकलन करने जैसे प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। हालिया मेटा जांच इस बात का संकेत है कि अब एल्गोरिदम स्वयं नियामकीय जांच का विषय बन चुका है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अपडेट

रीढ़ की हड्डी को चुपचाप नुकसान करती है एक्सियल अर्थराइटिस

कमर दर्द आज सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, लेकिन हर बार कमर दर्द केवल मांसपेशियों की थकान या गलत पोस्चर की ओर इशारा नहीं करता है। कुछ लोगों में लगातार रहने वाला दर्द शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी सूजन वाली बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इन्हीं बीमारियों में एक्सियल अर्थराइटिस (Axial Arthritis या Axial Spondyloarthritis) को शामिल किया जाता है। यह रोग धीरे-धीरे रीढ़ की हड्डी और सैक्रोइलियक जोड़ों में सूजन पैदा करता है, जिससे व्यक्ति रोजमर्रा के कार्यों को भी सही तरह नहीं कर पाता है। यदि समय पर इसका इलाज शुरू न किया जाए तो रीढ़ की हड्डी कठोर हो सकती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से चलने-फिरने भी मुश्किल हो सकती है।

एनआईएएमएस के अनुसार एक्सियल अर्थराइटिस एक क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी (लंबे समय तक चलने वाली सूजन संबंधी) रोग है, जो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी और सैक्रोइलियक जोड़ों को प्रभावित करती है। यह बीमारी स्पॉन्डायलोआर्थराइटिस ग्रुप का हिस्सा है। कई मरीजों की जांच में शुरुआती एक्स-रे सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन एमआरआई में सूजन स्पष्ट हो सकती है। इसलिए डॉक्टर कई बार इस तरह के लक्षण में एमआरआई की सलाह देते हैं। यह बीमारी केवल हड्डियों तक सीमित नहीं रहती बल्कि कुछ मरीजों में आंखों की सूजन त्वचा, आंत और जोड़ों पर भी असर डाल सकती है। अधिकतर मामलों में इसकी शुरुआत 45 वर्ष से पहले होती है।

शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचानें?: स्पॉन्डिलाइसिस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अनुसार एक्सियल अर्थराइटिस की पहचान शुरुआती लक्षणों से की जा सकती है, लेकिन अधिकांश लोग इन्हें सामान्य कमर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके शुरुआती संकेतों में लगातार तीन महीने से अधिक कमर दर्द,सुबह उठने पर 30 मिनट या उससे ज्यादा जकड़न, आराम करने से दर्द बढ़ना, व्यायाम या चलने से राहत मिलना, रात को गहरी नींद में दर्द के कारण आंख खुलना, कूल्हों में दर्द

लंबे समय तक बैठने के बाद उठने में कठिनाई, कुछ मरीजों में आंखों में लालिमा और दर्द, यदि ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो तुरंत रुमेटोलॉजिस्ट से जांच करानी चाहिए। एक्सियल अर्थराइटिस में दर्द सूजन के कारण होता है। इसमें आराम करने पर दर्द बढ़ सकता है, जबकि हल्की एक्सरसाइज या चलने से राहत मिलती है। सुबह की जकड़न लंबे समय तक बनी रहती है और समस्या महीनों तक जारी रह सकती है। यही कारण है कि इसमें केवल दर्द की दवा लेने के बजाय सही जांच और निदान जरूरी होता है।

निशाना

कभी ये ख़बर देख लेना...

धर्मराज देशराज

मिरे शहर को इक नज़र देख लेना
ज़रा साथ चल मेरा घर देख लेना।
मरे जा रहे हैं तुम्हे देखने को
ख़ुदारा हमें इक नज़र देख लेना।
न आँखों में आँसू न दिल को सुकूँ है
मुझे मेरे ऐ चारा-ग़र देख लेना।
यक़ीनन तेरे पास ख़त मेरा होगा
सलीके से तू नामावर देख लेना
तेरा मर्तबा रब से कम तो नही है
मेरी बेबसी राहबर देख लेना।
शिक़ायत जो बारिश की रब से करो तो
चमन में हैं कितने शजर देख लेना
'धरम' एक शायर हुआ था कहीं पे
छपेगी कभी ये ख़बर देख लेना।

यूजर्स गाइड

नॉर्मल स्विचबोर्ड या स्मार्ट टच पैनल लगाना, सभी के लिए अलग प्राथमिकता

घर को नया लुक देने के लिए या रिनोवेशन के समय यह ख्याल आता है कि साधारण स्विच बोर्ड की जगह टच पैनल वाले स्मार्ट स्विच लगवाए जाएं। दिखने में टच पैनल वाले स्मार्ट स्विच ज्यादा आकर्षक लगते हैं लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये साधारण स्विच से बेहतर होते हैं? इनकी लाइफ कितनी होती है और सबसे बड़ा सवाल कि इन्हें लगवाने में कितना खर्च आ सकता है। आमतौर पर घरों में पंखे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करने के लिए प्लास्टिक के बटन वाले स्विच बोर्ड इस्तेमाल में लिये जाते हैं।

नॉर्मल स्विच बोर्ड बजट के लिहाज से काफी किफायती होते हैं। 6 स्विच वाला एक मॉड्यूलर बोर्ड 300 से 800 रुपये की रेंज में अलग-अलग क्वालिटी में मिल जाता है। वहीं 6 टच स्विच वाला पैनल 2,500 से 6,000 रुपये तक का आता है। गौर करने वाली बात है कि एक नॉर्मल स्विच खराब हो, तो सिर्फ एक स्विच को बदला जा सकता है। वहीं अगर टच पैनल का एक स्विच खराब हो, तो पूरा का पूरा पैनल बदलना पड़ जाता है। जिसकी वजह स टच पैनल वाले स्मार्ट स्विच की मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है।

वैसे तो किसी भी स्विच बोर्ड की लाइफ उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है और सस्ते स्विच को महंगे स्विच के बराबर नहीं माना जा सकता। हालांकि एक साधारण स्विच की लाइफ 10-12 साल तक की होती है। वहीं स्मार्ट टच पैनल वाले स्विच की लाइफ 7 से 10 साल तक की मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार वोल्टेज कम या ज्यादा होने से इनका मदर बोर्ड खराब हो जाता है। वोल्टेज की समस्या आमतौर पर नहीं रहती, तो टचपैनल वाले स्विच 20 साल तक भी बिना किसी समस्या के काम कर सकते हैं। अगर बजट की समस्या नहीं है और आप चाहते हैं कि घर मॉडर्न के साथ-साथ लग्जरी भी दिखे, तो आप टच पैनल वाले स्मार्ट स्विच लगवा सकते हैं।

अगर आप कहीं से भी अपने घर के स्विच कंट्रोल करना चाहते हैं, तो भी स्मार्ट स्विच लगवाना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्रॉस कॉम्बिनेशन में स्विच इस्तेमाल करके आप मॉर्डन लुक्स और सहूलियत के बीच बैलेंस बना सकते हैं। इससे आपका बजट भी ज्यादा नहीं बढ़ता।

अजब - गजब

पहाड़ों में एक बार ही उगता है हिमालय का यह रहस्यमयी 'डायमंड' या कीमती फूल

हिमालय की बर्फीली और सुनसान चोटियों पर एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी 'डायमंड' उगता है। ये इतना बड़ा होता है कि इंसान से भी ऊंचा निकल जाता है। सुनने में ये भले ही किसी पौराणिक कहानी जैसा लगे, लेकिन कुदरत का ये करिश्मा कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक बेहद कीमती फूल है। इसे 'हिमालयन डायमंड' कहा जाता है। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर उगने वाला यह फूल रोज-रोज नजर नहीं आता। ये जमा देने वाली ठंड को 7 से 15 साल तक सहता है और अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार खिलता है। पहाड़ों में ट्रेकिंग करने वालों के लिए इस खिलते हुए फूल को देखना किसी बहुत बड़े सौभाग्य से कम नहीं होता।

स्थानीय लोग इस अनोखे पौधे को 'केनजो' या 'पदमचाल' कहते हैं। यह आम रंग-बिरंगे जंगली फूलों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता. पहाड़ों के पथरीले ढलानों और ग्लेशियरों के पास उगने वाला ये पौधा बेहद सब्र वाला है। ये रातों-रात या हर मौसम में नहीं उगता। इसे खिलने में 7 से 15 साल का लंबा वक्त लगता है. इतने सालों तक ये पौधा बर्फीली चट्टानों में खुद को बचाकर रखता है, फिर अपनी जिंदगी में केवल एक बार खिलता है। जैसे ही फूल खिलता है, ये अपने बीज हवा में बिखेर देता है और फिर इसका जीवन खत्म हो जाता है।

हीरा दुनिया की सबसे सख्त चीज मानी जाती है। ठीक वैसे ही ये फूल धरती के सबसे कठिन मौसम में मुस्कुराता है। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन 40 फीसदी तक कम होती है और हाड़-कांपने वाली हवाएं चलती हैं, वहां यह सीना ताने खड़ा रहता है। इस फूल के चारों तरफ पारदर्शी पत्तियों की एक परत होती है। ये धूप की गर्मी को अंदर सोख लेती है और बर्फीली हवाओं को रोकती है। बर्फ के बीच जब धूप इस पर पड़ती है तो ये बिल्कुल हीरे की तरह जगमगाता है।

अगर आप इस अजूबे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो जुलाई के अंत से सितंबर की शुरुआत का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मानसून में जब पहाड़ियों पर हल्की बारिश और धुंध होती है, तब ये पौधे खिलते हैं। इस रहस्यमयी फूल के वैली ऑफ फ्लावर्स (उत्तराखंड), हेमकुंड साहिब और गंगोत्री, नॉर्थ सिक्किम के लाचेन, लाचुंग और जीरो पॉइंट जैसे बेहद ऊंचे इलाकों में भी इसके खिलने की खबरें आती हैं। हाल ही में माउंट जोमोलहारी के बेस कैंप (4,300 मीटर) पर वैज्ञानिकों ने इसकी शानदार तस्वीरें ली हैं। हिमालय के वैद्यों और स्थानीय लोगों के लिए ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। सदियों से इसका इस्तेमाल जड़ी-बूटी के रूप में होता आ रहा है।

न्यूज विंडो

स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल एसपी ने निरीक्षण कर ली जानकारी

नर्मदापुरम। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आज सुबह पुलिस परेड ग्राउंड पर फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस. थोटा ने समारोह स्थल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान ध्वजारोहण से लेकर परेड की सलामी और परेड निरीक्षण तक का पूर्वाभ्यास किया गया। फाइनल रिहर्सल में स्कूली बच्चों ने पीटी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मैदान में नमी और कीचड़ होने के कारण बच्चों ने खड़े होकर पीटी का अभ्यास किया। इसके बावजूद बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ रिहर्सल में हिस्सा लिया।15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड पर जिले का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। एसपी ने समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। रिहर्सल के दौरान एडिशनल एसपी अभिषेक राजन और अपर कलेक्टर राजेश शुक्ला सहित अधिकारी मौजूद रहे। बता दे कि 15अगस्त पर जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह ने कलेक्टर सोमेश मिश्रा ध्वजारोहण करेंगे।

सिवनी के नेशनल हाइवे पर कार से चाकू लहराने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ा

सिवनी। जिले के नेशनल हाईवे-44 पर कार की खिड़की से चाकू लहराकर राहगीरों को डराने वाले दो युवकों को बंडोल पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से दो धारदार चाकू जब्त किए हैं। कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद की गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनके कब्जे से दो धारदार चाकू जब्त किए गए। बंडोल थाने में अपराध क्रमांक 307/26 और 308/26 दर्ज कर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

ड्यूटी पर नहीं पहुंचे एएसआई, सरकारी आवास में बिस्तर पर मिला शव

शहडोल। शहडोल जिले के कोतवाली थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) कैलाश मिश्रा (60) की गुरुवार सुबह पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह डायल-112 में ड्यूटी कर रहे थे। सुबह ड्यूटी पर नहीं पहुंचने और फोन रिसीव नहीं करने पर पुलिसकर्मी उनके आवास पहुंचे, जहां वह बिस्तर पर मृत अवस्था में मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस के अनुसार कैलाश मिश्रा पुलिस लाइन न्यू कॉलोनी के बी ब्लॉक स्थित कमरा नंबर 13 में अकेले रहते थे। देर शाम ड्यूटी खत्म करने के बाद वह अपने सरकारी आवास चले गए थे। गुरुवार तड़के उनके सीने में तेज दर्द हुआ था। इसके बाद उन्होंने डायल-112 को बुलाया और जिला अस्पताल पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार और दवा लेने के बाद वह वापस घर लौट आए थे। बताया गया कि सुबह डायल-112 में उनकी ड्यूटी शुरू होने का समय होने पर पायलट ने मोबाइल फोन से संपर्क किया, लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद कैलाश मिश्रा ने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद पायलट ने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र तिवारी पुलिस टीम के साथ पुलिस लाइन स्थित उनके आवास पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा खोलकर देखा गया तो कैलाश मिश्रा बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े मिले। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना देने के साथ उनके परिजनों को भी जानकारी दी।

नई हाइब्रिड व्यवस्था से किसानों को राहत; अब तारीख की सूचना फोन पर

खाद के लिए अब पंचायत में ही टोकन मोबाइल पर आएगा वितरण का मैसेज

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

खाद लेने के लिए किसानों को अब तहसील या संबंधित कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन ने खाद वितरण व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही टोकन देने की व्यवस्था शुरू की है। टोकन मिलने के बाद किसान के मोबाइल पर खाद लेने की तारीख का मैसेज भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर फोन से भी सूचना दी जाएगी।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन के निर्देश पर जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र में यह नई हाइब्रिड व्यवस्था लागू की गई है। एसडीएम, तहसीलदार और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में पंचायत भवनों में निर्धारित तारीख पर किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं। किसानों को टोकन वितरण की जानकारी दो दिन पहले पंचायत भवन में चस्पा करने के साथ गांव में मुनादी कराकर दी जा रही है। इससे किसान तय दिन और स्थान पर पहुंचकर टोकन ले सकेंगे। व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित गांव के पटवारी, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को दी गई है।

शिवपुर और खपरिया सर्किल में बांटे टोकन

बुधवार को शिवपुर सर्किल में पटवारी वैभव दुबे तथा खपरिया सर्किल में पटवारी प्रशांत यादव और गौरव शर्मा ने संबंधित ग्रामों में किसानों को खाद के टोकन वितरित किए। किसानों ने पंचायत स्तर पर शुरू की गई व्यवस्था को सुविधाजनक बताया।

ऑनलाइन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग

टोकन जारी होने के बाद खाद वितरण की तारीख मोबाइल संदेश और फोन के जरिए किसानों तक पहुंचाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के साथ पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।

बरखेड़ा स्कूल में शिक्षकों की कमी, बारिश में भीगते विद्यार्थियों ने दिया धरना

रतलाम/आलोट। दोपहर मेट्रो

ग्राम पंचायत बरखेड़ा कला स्थित शासकीय हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी और अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। बारिश के बीच भीगते हुए छात्रों ने धरना देकर अपनी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी एवं एसडीएम आलोट के नाम नायब तहसीलदार राजेश पाटीदार को सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक न होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों और छात्रों ने शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा अध्यापन व्यवस्था सुचारु करने की मांग की। छात्रों का कहना था कि आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों के अभाव में उन्हें पढ़ाई में परेशानी हो रही है। ज्ञापन में शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ ही अध्यापन के लिए पर्याप्त कक्षा-कक्ष, लेबोरेटरी रूम तथा भूगोल, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की अलग-अलग लैब उपलब्ध कराने की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि एक्सपेरिमेंटशालाओं और पर्याप्त शिक्षकों से उन्हें विषयों की बेहतर समझ मिलेगी और शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा। अपनी मांगों को लेकर छात्र बारिश में भी डटे रहे। पानी में भीगते हुए विद्यार्थियों ने प्रशासन से विद्यालय की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। छात्रों का कहना था कि वे विरोध के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

तेज रफ्तार जीप अनियंत्रित होकर पलटी, 6 लोग घायल

पांढुर्णा। दोपहर मेट्रो

पांढुर्णा के परसोडी बायपास पर आज गुरुवार सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन में सवार महाराष्ट्र के सावनेर-खापा क्षेत्र के 6 लोग घायल हो गए। परिवार पचमढ़ी के नागद्वार मेले से दर्शन कर अपने घर लौट रहा था। चालक के अनुसार, परसोडी बायपास से गुजरते समय अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और स्कॉर्पियो सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

रायसेन जिले में खाद के लिए हो रहे परेशान किसान

रायसेन। दोपहर मेट्रो

बरेली खाद की परेशानी को लेकर किसानों ने आज कृषि उपज मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया एसडीएम तहसीलदार एसडीओपी सहित प्रशासन मौके पर पहुचा लेकिन बगैर नतीजा निकले बापिस लोटे किसानों ने मंडी के गेट के ताले को तुड़वा रहे एसडीएम अंकित जैन पर पानी फेका ओर पत्थर भी मारा एसडीएम बाल बाल बचे खाद वितरण केंद्र प्रभारी कमलेश पटेल बीते 15 वर्षों से जमे हुए है किसानों ने साफ कहा कमलेश पटेल को यहां से हटाया जाए , एसडीएम बोले व्यवस्था बना रहे है। एसडीएम अंकित जैन को गेट कूदकर बाहर निकले प्रशासान अगर चाहे तो किसान परेशान ना हो अगर खाद सोसायटियों को दिया जाए तो एक जगह भीड़ ना हो पर प्रशासान इस ओर ध्यान नही दे रहा । आखिरकार किसान आपस मे भिड़े ओर ताला टूटा ।

रायसेन जिले के बरेली में खाद की समस्या विकराल रूप ले रही है प्रशासनिक अक्षमता बन रही बजह खाद वितरण केंद्र एक जगह होने की बजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हजारों किसान और केंद्र एक खाद वितरण केंद्र प्रभारी कमलेश पटेल किसानों को टोकन बाटने के बाद भी परेशान कर रहा है ऐसा आरोप किसान लगा रहे है। बीते चार दिन से किसान लाइन में लगकर खाद लेने की जदोजहद कर रहा है बावजूद इसके खाद नही मिल पा रही किसान परेशान है एक माह से ज्यादा धान की फसल लगे हो गया अब खेत मे खाद डालना है समय पर खाद नही मिला तो किसानों की फसल नष्ट हो जाएगी किसानों का आरोप है कि खाद वितरण केंद्र प्रभारी कमलेश पटेल किसानों को परेशान करता है और अपने पहचान बालो को खाद जल्द दे देता है किसान चार चार दिन लाइन में लगा रहता है।

मंडला के खेरी में बने विपणन गोदाम नंबर-5 में लाखों रुपए का गेहूं खराब

मंडला। दोपहर मेट्रो

मंडला के खेरी में बने विपणन गोदाम नंबर-5 में लाखों रुपए का गेहूं खराब होने की खबर आई है। गोदाम में रखे गेहूं में कीड़े लगने की वजह से वह आटा बनने लगा है। साल 2025-26 में नागरिक आपूर्ति निगम ने करीब 35,787 बोरियां यानी 17,859 क्विंटल गेहूं खरीदकर इस गोदाम में रखवाया था, जिसमें से तीन ढेर (स्टैक) में रखा गेहूं खराब होने की जानकारी मिली है।

नशामुक्त भारत के साथ आध्यात्मिक मूल्यों से समृद्ध समाज का निर्माण संस्था का लक्ष्य: ब्रह्माकुमारी रेखा

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, चर्च वाली गली वरेठ रोड स्थित सेवा केंद्र द्वारा 10 करोड़ नशामुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत पत्रकार भवन में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं अभियान के पोस्टर अनावरण के साथ हुआ। यह राष्ट्रव्यापी अभियान संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका परम श्रद्धेय दादी प्रकाशमणि की पुण्य स्मृति में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बीके रुक्मणी दीदी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जनजागरण के माध्यम से समाज को नशामुक्त बनाना तथा प्रत्येक नागरिक को इस सामाजिक परिवर्तन में सहभागी बनाना है। नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा चलाया जा रहा यह महाअभियान सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक बनता है। मानव जीवन अमूल्य है, इसलिए इसे नशे में नष्ट करने के बजाय समाज और राष्ट्रहित में लगाना चाहिए।

व्यापार महासंघ अध्यक्ष विपिन तिवारी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों से नशामुक्ति का संकल्प लेना महज अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का महायज्ञ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जागरूकता से परिवार और समाज में नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने कहा कि यदि सामूहिक प्रयास से एक भी व्यक्ति को नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जा सके तो यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य होगा। ब्रह्माकुमारी रेखा दीदी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि वास्तविक नशामुक्ति का आधार आत्मजागृति और ईश्वर से जुड़ाव है। उन्होंने उपस्थित लोगों को राजयोग ध्यान का अभ्यास भी कराया।

मेट्रो एंकर वृक्षों को रक्षासूत्र बांधकर सुरक्षा का लिया संकल्प

हरियाली अमावस्या पर नपा प्रशासन ने मुक्तिधाम परिसर में रोपे नए पौधे

सिरोंज। दोपहर मेट्रो

हरियाली अमावस्या के अवसर पर नपा प्रबंधन ने जनप्रतिनिधियो एवं मोक्षधाम सेवा समिति के सदस्यों के साथ मुक्तिधाम परिसर पहुंचकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने परिसर में पूर्व में लगाए गए पौधे जो अब वृक्ष बनते जा रहे है उनका पूजन कर रक्षा सूत्र भी बांधे। इस अवसर पर करीब पांच सौ नए पौधों को परिसर में रोपने का लक्ष्य रखा गया है ।

लटेरी रोड स्थित मुक्तिधाम परिसर में विगत वर्षों से विधायक उमाकांत शर्मा के मार्गदर्शन में जनसहयोग से विकास कार्य कराकर स्वच्छ एवं सर्वसुविधायुक्त मुक्तिधाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है इसी श्रृंखला में शासन द्वारा दिए गए वृक्षारोपण लक्ष्य के अंतर्गत नपा प्रशासन ने मिले लक्ष्य अनुसार स्थान चयनित किए हैं। इसके पूर्व भी समिति के सदस्यों द्वारा विगत वर्षों में लगाए गए पौधे जो अब वृक्ष बनने की कगार पर है तथा फूलदार होकर परिसर की सुंदरता बढ़ाने लगे हैं उनका हरियाली अमावस्या के अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं साजसेवियों ने पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले वृक्षों एवं भगवान शिवपार्वती की श्रद्धा भाव के साथ पूजन किया गया तथा वृक्षों को रक्षासूत्र बांधकर उनके संवर्धन करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर कदम, गुलमोहर, बिल्वपत्र, बुगनबेलिया सहित फूलदार पौधे शामिल हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नपाध्यक्ष मनमोहन साहू, स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि राजा मियां,एल्डरमैन सुमंत मित्तल,बृजमोहन नामदेव, रोहित रघुवंशी,नपा सीएमओ रामप्रकाश साहू, बद्री प्रसाद शर्मा, ईंजीनियर अखिलेश मार्को मोक्षधाम सेवा समिति सदस्य राकेश भार्गव,सचिन शर्मा,भारत सिंह धाकड़ शेरसिंह राजपूत,श्यामकुमार साहू सहित नागरिकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

न्यूज विंडो

शहर में निकली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, जगह-जगह किया स्वागत

धार। आजादी के महापर्व 80 वे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहर में एकता, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम का संदेश देने के लिए भव्य भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत जोडो तिरंगा यात्रा के दौरान सभी कांग्रेसी दोपहर 2 बजे शहीद चौराहे पर एकत्रित हुए। जहां वरिष्ठजनों ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा शुरूआत की। भारत जोडो तिरंगा यात्रा में हजारों युवा व शहरवासी देशभक्ति के रंग में उत्साह पूर्वक प्रमुख मार्गों से झुमते, गाते वाहनों से निकले थे। लगभग दो किलोमीटर लंबी इस यात्रा में शहर के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों के साथ-साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा के दौरान शहर का माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मुख्य मार्गों से गुजरी इस यात्रा का स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों द्वारा दो दर्जन से अधिक स्थानों पर मंच बनाकर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान देश भक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा था। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यत मनोज सिंह गौतम, शंकर चौहान, अजित पाल सिंह चौहान, रत्ने श जांगडे, राकेश डोड, बंटी डोड, श्रीजीत तोमर, करीम कुरैशी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।

हरियाली अमावस्या के अवसर पर हरियाली यात्रा का आयोजन

तेंदूखेड़ा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में नवांकुर संस्था सूर्य सेवा समिति झरोली के नेतृत्व में हरियाली अमावस्या के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरूकता को लेकर हरियाली यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम के दुर्गा मंदिर चबूतरे पर परिषद द्वारा चयनित नवांकुर सखियों एवं ग्रामीणजनों की उपस्थिति में की गई। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच वीरेंद्र सिंह गौड़, शिक्षक मुकेश जैन, वरिष्ठ समाजसेवी रमेश केवट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गीता साहू, सूर्य सेवा समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह केवट, सचिव रामदास, उपसरपंच किशन केवट, पूर्व सरपंच कमोद सिंह, एसवीएम ब्लॉक समन्वयक महेंद्र धुर्वे एवं विकासखंड समन्वयक दीपचंद मालवीय सहित अनेक ग्रामीणजन उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा हरियाली, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं नशामुक्ति के संबंध में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई तथा इन विषयों पर अपने विचार साझा किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रीतम सिंह केवट ने किया।

बालाघाट में आदिवासी इलाकों में रहस्यमयी बीमारी से अब तक आठ बच्चों की गई जान

बालाघाट। दोपहर मेट्रो

जिले के आदिवासी इलाकों में रहस्यमयी बीमारी के चलते 26 जून से अब तक 8 बच्चों की जान चली गई है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज और बालाघाट के डॉक्टरों की टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लेकिन मौतों की असली वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। टीम के मुताबिक, बीमार बच्चों में न्युमोनिया, एनीमिया यानी खून की कमी, डिहाइड्रेशन, बुखार, खुजली, मलेरिया और किडनी पर असर जैसे लक्षण मिले हैं। सैंपल पुणे की लैब में भेजे गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हालांकि, यह रिपोर्ट कब तक आएगी, इस पर स्वास्थ्य विभाग कुछ भी बोलने से बच रहा है।

खुलेआम चल रहे अहातों के खिलाफ देर रात चलाया अभियान

जबलपुर। दोपहर मेट्रो

अवैध शराब की बिक्री और खुलेआम चल रहे अहातों के खिलाफ जबलपुर पुलिस ने बुधवार देर रात अभियान चलाया। रांझी क्षेत्र में सीएसपी सतीष साहू और थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बापू नगर, बड़ा पत्थर, मोहनिया, रक्षा नगर समेत एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई देर रात करीब 2 बजे तक चली। पुलिस को कई दुकानों से अवैध रूप से शराब बेचने की जानकारी मिली। कुछ जगह लोग शराब पीते हुए भी मिले। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पकड़ा। कुछ युवकों को कान पकड़कर उठक-बैठक भी लगवाई गई।

मेट्रो एंकर | बदनावर में अरविंद ग्रुप लगाएगा 1200 करोड़ की इकाई

105 एकड़ जमीन आवंटित, एक साल के भीतर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद

धार। दोपहर मेट्रो

गुजरात दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुलिन एस. लालभाई और वाइस चेयरमैन पुनीत लालभाई से मुलाकात की। बैठक में अरविंद ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में तीन स्थानोंदेवास जिले के बरलाई, धार जिले के बदनावर स्थित पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क और बेटमा में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की योजना पर चर्चा हुई।

धार जिले के लिए यह निवेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बदनावर में स्थापित पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क में अरविंद लिमिटेड को 105 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कंपनी यहां लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्क में एक वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इकाई के शुरू होने से धार जिले और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अरविंद ग्रुप की इकाइयों से मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा। इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ राज्य की टैक्स आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच औद्योगिक एवं कारोबारी संबंध और मजबूत होंगे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्योग नीरज मंडलोई, उद्योग सचिव जॉन किंग्सले और एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि अरविंद लिमिटेड द्वारा पीएम मित्र पार्क में निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के तहत कंपनी को उपलब्ध निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी दी गई, जिनमें पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए सहायता शामिल है। जानकारी के अनुसार, इंदौर में संचालित पेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के अनुबंध के तहत प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। बैठक में सीसीआईपी के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने तथा शासन स्तर पर प्रस्ताव के त्वरित परीक्षण और अनुमोदन की कार्रवाई पर भी विचार-विमर्श किया गया।

तेजगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में तीन मवेशियों की मौत

गुस्साएं लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

तेजगढ़ थाना क्षेत्र में रात तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर जा रही छह भैंसों को टक्कर मार दी। हादसे में तीन भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं, हादसे के दौरान भैंसों का मालिक उत्तम यादव बाल-बाल बच गया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, कंसा हरई के बीच यादव ढाबा के समीप रात करीब सात से आठ बजे के बीच उत्तम पिता रम्मू यादव अपनी छह भैंसों को चराकर घर लौट रहा था तभी दमोह की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने भैंसों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गईं। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

दो भैंस थी गर्भवती, परिवार में आर्थिक संकट

भैंस मालिक उत्तम यादव के अनुसार टक्कर मारने वाला ट्रक गैस सिलेंडरों से लदा हुआ था। उसके पास ट्रक का नंबर भी है और हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर जबलपुर की ओर भाग गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद दोपहर करीब एक बजे उत्तम यादव के परिजन मुख्य मार्ग पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इससे मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलने पर तेजगढ़ थाना प्रभारी अरविंद लोधी, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी और पटवारी मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उत्तम यादव और उसके पिता रम्मू यादव से चर्चा की। रम्मू यादव ने बताया कि उनके परिवार का भरण-पोषण भैंसों से ही होता था। छह भैंसों में दो गर्भवती थीं, जिनमें एक की मौत हो गई और दूसरी घायल है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को उचित कार्रवाई और मदद का आश्वासन दिया।

पुलिस ने ट्रक की तलाश शुरू की

तेजगढ़ थाना प्रभारी ने ट्रक की तलाश कर कार्रवाई करने की बात कही। आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया और मार्ग पर आवागमन शुरू हो गया जाम खुलने के बाद दोनों ओर फंसे दर्जनों वाहन निकल सके। वाहन चालकों ने बताया कि उन्हें करीब एक घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। तेजगढ़ थाना प्रभारी अरविंद लोधी ने बताया कि उत्तम पिता रम्मू यादव छह भैंसों को लेकर रात घर लौट रहा था, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में तीन भैंसों की मौत और तीन घायल हुई हैं। मृत भैंसों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीड़ित की शिकायत और उपलब्ध ट्रक नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

आबकारी विभाग की निगरानी पर उठे सवाल, उपभोक्ता संरक्षण विभाग की चुप्पी

ओवररेट शराब की बिक्री, एमआरपी पर भारी वसूली

कोतमा। दोपहर मेट्रो

कोतमा क्षेत्र में शराब दुकानों पर निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने के आरोप सामने आने के बाद आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कई मामलों में बोतल पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा रकम वसूली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शराब की बोतल पर एमआरपी स्पष्ट रूप से अंकित है, तो उससे अधिक कीमत पर बिक्री कैसे हो रही है? क्या संबंधित विभाग की नियमित जांच में यह बात सामने नहीं आती, या फिर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही?

शराब दुकानों की निगरानी और लाइसेंस शर्तों के पालन को लेकर आबकारी विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुकानों पर नियमित निरीक्षण के दौरान बोतल की एमआरपी और ग्राहक से वसूली गई राशि का मिलान क्यों नहीं किया जाता। वहीं उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े पहलुओं को लेकर उपभोक्ता संरक्षण तंत्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि उपभोक्ताओं से निर्धारित कीमत से अधिक राशि ली जा रही है, तो शिकायतों की जांच और नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ओवररेट की शिकायतों के बीच यह भी जांच का विषय है कि शराब खरीदने वाले ग्राहकों को बिल/रसीद नहीं दी जा रही है ग्राहक से एमआरपी से अधिक राशि ली गई है, तो उसके पास शिकायत दर्ज कराने के लिए बिक्री का प्रमाण होना जरूरी है। आबकारी विभाग कोतमा क्षेत्र की शराब दुकानों का अचानक निरीक्षण करे और अलग-अलग ब्रांड की बोतलों पर अंकित एमआरपी तथा ग्राहकों से ली जा रही वास्तविक कीमत का मिलान करे। कोतमा क्षेत्र में शराब दुकानों की काउंटर बिक्री व्यवस्था को लेकर एक और सवाल खड़ा हो रहा है। आबकारी विभाग द्वारा काउंटर बिक्री के लिए जिस व्यक्ति को अधिकृत अथवा स्वीकृत किया गया है, काउंटर पर शराब बेचते समय कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या काउंटर पर शराब बेचने वाले व्यक्ति का नाम आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या उसे विधिवत अनुमति या अधिकृत किया गया है। बिक्री करने वाला व्यक्ति अधिकृत नहीं है।

डिंडौरी में बाइक में अचानक भड़की आग

डिंडौरी। दोपहर मेट्रो

डिंडौरी कलेक्ट्रेट तिराहे के समीप पंजाब नेशनल बैंक के सामने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तान सिंह ठाकुर की बाइक में अचानक आग लग गई। चलती बाइक से धुआं उठते ही उपाध्यक्ष ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।

टेस्ट सीरीज : गॉल में 15 अगस्त से शुरू होगा महामुकाबला

भारत की अग्निपरीक्षा, सरफराज-जुरेल में नं.-6 की जंग; गेंदबाजी संयोजन पर भी सस्पेंस

गॉल, एजेंसी

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम की तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में यह सीरीज भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में पहले टेस्ट की अंतिम एकादश को लेकर टीम प्रबंधन के सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल छठे नंबर के बल्लेबाज का है, जहां सरफराज खान और ध्रुव जुरेल के बीच मुकाबला है। दूसरा सवाल गेंदबाजी संयोजन को लेकर है कि भारत तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा या अतिरिक्त स्पिनर को मौका देगा।

पडिक्कल ने तीसरे नंबर का दावा मजबूत किया- चोटिल साई सुदर्शन की अनुपस्थिति में देवदत्त पडिक्कल को टीम में मौका मिला है। उन्होंने अभ्यास मैच में नाबाद 142 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। उनके प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि तीसरे नंबर पर उनकी जगह लगभग तय हो सकती है। इससे टीम प्रबंधन का मुख्य ध्यान अब छठे नंबर के बल्लेबाज के चयन पर केंद्रित हो गया है।

जुरेल के पास अनुभव, लेकिन हालिया प्रदर्शन चिंता बढ़ाने वाला-

ध्रुव जुरेल भारत के लिए अब तक 10 टेस्ट खेल चुके हैं। उन्होंने 34.14 की औसत से 478 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। विकेटकीपिंग के अलावा उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए उपयोगी मानी जाती है। हालांकि, हालिया प्रदर्शन उनके पक्ष में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन के बाद अगली टेस्ट सीरीज में जुरेल 14, 13, 0 और 2 रन ही बना सके। ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने दोनों टेस्ट की दोनों पारियों में उन्हें आउट किया। श्रीलंका में अभ्यास मैच में भी जुरेल 1 और 17 रन ही बना सके तथा रमेश मेंडिस का शिकार बने। गॉल की संभावित स्पिन मददगार पिच को देखते हुए यह आंकड़ा टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

सरफराज के आंकड़े दे रहे मजबूत तर्क

दूसरी ओर सरफराज खान के पक्ष में उनका शानदार प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने 62 प्रथम श्रेणी मैचों में 5,114 रन बनाए हैं। उनका औसत 64.73 है और खाते में 17 शतक दर्ज हैं। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी को भी उनकी बड़ी ताकत माना जाता है। सरफराज ने भारत के लिए अब तक छह टेस्ट की 11 पारियों में 371 रन बनाए हैं। श्रीलंका की परिस्थितियों में स्पिन को खेलने की उनकी क्षमता उन्हें जुरेल पर बढ़त दिला सकती है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ भी छठे नंबर के लिए जुरेल की जगह सरफराज को प्राथमिकता देने की राय दे चुके हैं।

गेंदबाजी संयोजन पर भी बड़ा फैसला

भारतीय टीम की परेशानी केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का तेज गेंदबाजी आक्रमण संभालना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन तीसरे तेज गेंदबाज को खिलाया जाए या एक अतिरिक्त स्पिनर को मौका दिया जाए, इस पर फैसला बाकी है। गॉल की पिच आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन उमस और परिस्थितियों के कारण तेज गेंदबाजों को हवा में स्विंग भी मिल सकती है। कई क्रिकेट विशेषज्ञ सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार के साथ तीन तेज गेंदबाजों के संयोजन के पक्ष में हैं। नीतीश कुमार रेड्डी उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिरिक्त तेज गेंदबाजी विकल्प रखना भी टीम के लिए उपयोगी हो सकता है।

गॉल में चयन पर सबकी नजर

पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम के सामने तस्वीर काफी हद तक साफ है, लेकिन छठे नंबर और गेंदबाजी संयोजन के फैसले अंतिम समय तक रोमांच बनाए रखेंगे। एक तरफ जुरेल का टेस्ट अनुभव है, तो दूसरी तरफ सरफराज का प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड और स्पिन के खिलाफ मजबूत खेल उन्हें दावेदार बनाता है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में भारत के लिए श्रीलंका दौरा महत्वपूर्ण है। ऐसे में गॉल में चुनी जाने वाली अंतिम एकादश केवल एक मैच का फैसला नहीं होगी, बल्कि आने वाले मुकाबलों में टीम की रणनीति और प्राथमिकताओं की झलक भी देगी।

भारत-श्रीलंका टेस्ट कार्यक्रम

पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त, गॉल
दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त, कोलंबो

तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे

दिल्ली में गूंजेगा भारत-अफगानिस्तान का टी20 रण, 13 सितंबर से आगाज

पहली बार भारत में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान,

नई दिल्ली, एजेंसी

बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्तावित तीन मैचों की टी20 सीरीज की तारीखों को मंजूरी दे दी है। दोनों टीमों के बीच यह सीरीज 13 से 17 सितंबर के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा मैच 17 सितंबर को होगा। यह सीरीज अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए खास महत्व रखती है, क्योंकि यह पहला अवसर होगा जब अफगानिस्तान भारत में टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और अब दोनों टीमें तीनों प्रारूपों में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करती नजर आएंगी।

बीसीसीआई ने जताई साझेदारी की प्रतिबद्धता

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि भारतीय बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास को समर्थन देने और उसके खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर खेलने के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय सीरीज खिलाड़ियों को मजबूत टीमों के खिलाफ नियमित रूप से खेलने और महत्वपूर्ण अनुभव हासिल करने का अवसर देती हैं। उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अभी काफी संभावनाएं हैं। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच पिछले वर्षों में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं।

पंड्या के गुजरात टाइटन्स कमबैक पर ब्रेक, शुभमन गिल ने कर दिया खेला!

नई दिल्ली, एजेंसी

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या के आईपीएल भविष्य को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पंड्या ने अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटन्स में वापसी की कोशिश की थी। गुजरात फ्रेंचाइजी भी उन्हें दोबारा टीम में शामिल करने के लिए तैयार थी, लेकिन कप्तानी को लेकर दोनों पक्षों के बीच बात अटक गई। हार्दिक की इच्छा थी कि गुजरात लौटने पर उन्हें फिर से टीम की कमान सौंपी जाए, जबकि फ्रेंचाइजी इसके लिए तैयार नहीं हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात टाइटन्स हार्दिक को टीम में वापस लेने के विकल्प पर विचार कर रही थी। इस संबंध में मौजूदा कप्तान शुभमन गिल से भी बातचीत की गई। गिल ने हार्दिक की वापसी पर कथित तौर पर सहमति जताई थी, लेकिन जैसे ही कप्तानी का मुद्दा सामने आया, मामला आगे नहीं बढ़ सका। गुजरात फ्रेंचाइजी ने हार्दिक को टीम में शामिल करने की संभावना पर आपत्ति नहीं जताई,

लेकिन कप्तानी की उनकी शर्त स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिलहाल हार्दिक की गुजरात वापसी को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। गुजरात टाइटन्स के एक प्रतिनिधि ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। वहीं, हार्दिक के प्रवक्ता ने कहा कि खिलाड़ी ने किसी फ्रेंचाइजी से सीधे तौर पर ट्रांसफर या ट्रेड को लेकर बातचीत नहीं की है। उनके मुताबिक, यदि हार्दिक को लेकर किसी तरह का संपर्क हुआ है तो वह मुंबई इंडियंस के माध्यम से हुआ है।

स्क्वैश- पीएसए चैलेंजर टूर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे तन्वी-सूरज

कोलकाता। कोलकाता में आयोजित एचसीएल स्क्वैश पीएसए चैलेंजर टूर में महिलाओं की शीर्ष वरीयता प्राप्त तन्वी खन्ना और पुरुष वर्ग के चौथी वरीयता प्राप्त सूरज कुमार चंद सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपनी ही देश की छठी सीड निरुपमा दुबे को सीधे गेम में शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मिस्र की तीसरी सीड सोहायला हजेम से होगा। वहीं, सूरज चंद ने आठवें सीड ओम सेमवाल को चार गेम में हराया। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का सिंगल्स खिताब जीतने वाले सूरज अब सेमीफाइनल में मिस्र के टॉप सीड मोहम्मद गोहर का सामना करेंगे। इससे पहले मंगलवार को, सूरज चंद ने पुरुषों के प्री-क्वार्टर फाइनल में मिस्र के हसन मेनशावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से हराया। यह मुकाबला 73 मिनट तक चला।

ओसाका की चुनौती पड़ी फीकी, राइबाकिना ने पलटवार कर सेमीफाइनल में मारी एंट्री

मॉन्ट्रियल, एजेंसी

एलेना राइबाकिना ने शानदार जुझारूपन का प्रदर्शन करते हुए नाओमी ओसाका को तीन सेट के रोमांचक मुकाबले में हराकर कैनेडियन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। एक सेट से पिछड़ने के बाद राइबाकिना ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी की और ओसाका को 4-6, 7-6 (5), 6-4 से शिकस्त दी।

मुकाबले की शुरुआत में ही ओसाका ने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने राइबाकिना की पहली सर्विस गेम में ब्रेक हासिल कर शुरुआती बढ़त बना ली। राइबाकिना के पास अगले गेम में वापसी का मौका था, लेकिन ओसाका ने तीनों ब्रेक पॉइंट बचा लिए। इसके बाद राइबाकिना को सेट में दोबारा ब्रेक का मौका नहीं मिला और ओसाका ने पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में राइबाकिना ने अपनी लय वापस हासिल की। हालांकि शुरुआती सर्विस गेमों में उन्हें परेशानी हुई और दो बार ब्रेक का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी ओसाका की सर्विस तोड़कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ और सेट टाईब्रेकर तक पहुंचा। राइबाकिना ने दबाव में शानदार खेल दिखाते हुए टाईब्रेकर 7-5 से जीत लिया और मुकाबले को निर्णायक तीसरे सेट में पहुंचा दिया।

तीसरे सेट में आया बड़ा टर्निंग

तीसरे सेट में ओसाका 3-2 से आगे थीं और राइबाकिना को ट्रिपल ब्रेक पॉइंट का सामना करना पड़ा। यह मुकाबले का सबसे अहम क्षण साबित हुआ। राइबाकिना ने धैर्य नहीं खोया और कुल चार ब्रेक पॉइंट बचाकर अपनी सर्विस बरकरार रखी। इसके बाद मुकाबले का मोमेंटम पूरी तरह उनके पक्ष में चला गया। ओसाका पर दबाव बढ़ता गया और 4-3 के स्कोर पर राइबाकिना ने उनकी सर्विस तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने शानदार सर्विस और आक्रामक शॉट्स के दम पर मैच खत्म किया।

मनोरंजन | **बॉलीवुड का कोना**

उम्र बढ़ी तो और निखरी ईशा कोप्पिकर! अभिनेत्री ने साझा की स्टाइलिश तस्वीरों की सीरीज

फिटनेस से मातृत्व और प्यार तक जिंदगी के हर रंग पर खुलकर रखी बात

उम्र को लेकर समाज की सोच भले धीरे-धीरे बदल रही हो, लेकिन अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने अपनी जिंदगी और अनुभवों से इस बदलाव को एक अलग अंदाज में सामने रखा है। सोशल मीडिया पर अपनी स्टाइलिश तस्वीरों की सीरीज साझा करते हुए ईशा ने उम्र, आत्मविश्वास, फिटनेस, मातृत्व, प्यार और रिश्तों को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उनका संदेश साफ है-उम्र सिर्फ संख्या है और असली खूबसूरती खुद को हर पड़ाव पर बेहतर बनाने में है।

ईशा ने अपनी तस्वीरों के साथ लिखा कि उम्र के साथ वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और अपनी पसंद को लेकर सजग हुई हैं। उनके मुताबिक, खूबसूरती और अंदाज का उम्र से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान समय के साथ खुद को कितना निखारता है।

उन्होंने कहा कि अब वह बेहतर चुनाव करती हैं, जिंदगी को अधिक गहराई से महसूस करती हैं और हर पड़ाव को खास बनाने की कोशिश करती हैं। ईशा ने अपने अंदाज में कहा कि वह वही लड़की हैं, लेकिन अब उनके स्टैंडर्ड बेहतर, सपने बड़े और यादें पहले से ज्यादा हैं। ईशा ने वर्कआउट से जुड़ी तस्वीर भी साझा की। इसमें वह व्यायाम करती नजर आईं। उन्होंने फिटनेस को कुछ समय के लिए अपनाई जाने वाली आदत नहीं, बल्कि जीवनशैली बताया। उनका कहना है कि दो दशक बाद भी वह खुद को फिट रखने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं।

मां बनने के बाद भी खुद को नहीं भूलीं

अभिनेत्री ने मातृत्व को अपनी जिंदगी का खास हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मां होना बेहद खूबसूरत अनुभव है, लेकिन इसके साथ अपने भीतर मौजूद उस लड़की को जिंदा रखना भी जरूरी है, जो अपने सपनों और पसंद को लेकर उत्साहित रहती है। प्यार और रिश्तों पर भी ईशा ने अपनी सोच साझा की। उन्होंने कहा कि वह आज भी प्यार से मिलने वाली खुशी और खास एहसास पर विश्वास करती हैं, लेकिन अब रिश्तों को लेकर उनकी पसंद और उम्मीदें पहले से अधिक स्पष्ट और बेहतर हैं। ईशा ने यादों को लेकर भी दिलचस्प बात कही। उनके मुताबिक, जिंदगी में सिर्फ तस्वीरें जमा करने के बजाय खूबसूरत यादें संजोना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अब तस्वीरें भी काफी अच्छी आती हैं।

मीनाक्षी शेषाद्रि का पुराना अंदाज फिर छाया 'बहुत जताते हो चाह हमसे' ने मचाई धूम

अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म आदमी खिलौना है के दिनों को याद किया। अभिनेत्री ने इस पोस्ट के जरिए फिल्म में फिल्माया गया गाना बहुत जताते हो, चाह हमसे के पीछे की स्टोरी बताई।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें वे बहुत जताते हो, चाह हमसे पर डांस कर रही हैं। वीडियो में अभिनेत्री शानदार एक्सप्रेशन और डांस मूव्स के साथ डांस कर रही हैं। अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, ÷यह बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना है। यह गाना मेरी फिल्म %आदमी खिलौना है% से लिया गया है। महाबलेश्वर की हसीन वादियों में इस गाने को फिल्माया गया था। नदीम श्रवण का ये गीत बेहद पसंद किया गया। इसे दोबारा फिल्माने में बहुत मजा आया। अभिनेत्री के इस वीडियो ने फैंस को पुराने दिनों का एहसास करवा दिया। गाना बहुत जताते हो, चाह हमसे की बात करें, तो यह साल 1993 की बॉलीवुड फिल्म आदमी खिलौना है का एक बेहद प्रसिद्ध रोमांटिक गाना है। इस गाने को मशहूर गायक मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी थी और इसके बोल समीर ने लिखे थे। इसका संगीत नदीम-श्रवण की प्रसिद्ध जोड़ी ने तैयार किया था।

यह गाना प्यार, अपनेपन और दिल की गहराइयों में छिपे जज्बातों को बयां करता है। इसके बोल प्रेमी-प्रेमिका के बीच के मीठे अहसासों, शिकायत और एक-दूसरे के साथ जीने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 90 के दशक का यह मेलोडी सॉन्ग आज भी अपने कर्णप्रिय संगीत के लिए पसंद किया जाता है। 1993 में रिलीज हुई पारिवारिक और भावनात्मक हिंदी ड्रामा फिल्म आदमी खिलौना है का निर्देशन जे. ओम प्रकाश ने किया और संगीत नदीम-श्रवण ने दिया था।

मेट्रो बाजार

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में शहरीकरण अहम

तिरुवनंतपुरम । 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत के आर्थिक परिवर्तन और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने में शहरीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजभवन द्वारा आयोजित 'विकसित भारत 2047 के लिए विकास के इंजन के रूप में शहरी क्षेत्र' विषय पर लोक भवन कन्वर्सेशन के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए पनगढ़िया ने कहा कि भारत के 30 ट्रिलियन डॉलर की विकसित और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य उत्पादक, मजबूत और कुशल तरीके से संचालित शहरों के बिना हासिल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि लगभग हर विकसित देश में शहरीकरण का स्तर ऊंचा है। भारत का भी शहरी विकास का लंबा इतिहास रहा है और उसे शहरीकरण को आगे बढ़ाने को लेकर संकोच नहीं करना चाहिए। पनगढ़िया ने कहा कि शहरीकरण का उद्देश्य केवल मौजूदा शहरी आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार तक सीमित नहीं होना चाहिए। शहरों को कारोबार और रोजगार के अनुकूल बनाना होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित किया जा सके और रोजगार के अवसर पैदा हों।

उन्होंने कहा, आर्थिक गतिविधियां शहरीकरण को बढ़ावा देती हैं।उन्होंने जोर दिया कि रोजगार सृजन से ग्रामीण बस्तियों और बड़े शहरों एवं कस्बों के आसपास के क्षेत्रों को भी जीवंत शहरी क्षेत्रों में बदलने में मदद मिलेगी। पनगढ़िया ने कहा कि शहरी जमीन की कमी और उसकी ऊंची लागत भारतीय शहरों में आर्थिक गतिविधियों के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से हैं।

नई क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में हेरफेर के कोई सबूत नहीं मिले, यह बाजार के लिए बड़ा सुधार

मुंबई । सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने बुधवार को कहा कि शेयर बाजारों में हाल ही में लागू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) में किसी प्रकार की हेरफेर या अनियमितता के प्रमाण नहीं मिले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भारतीय पूंजी बाजार की संरचना में किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो देश के बाजारों को वैश्विक मानकों के और करीब लाता है।

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन भारतीय पूंजी बाजार की संरचना में किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो भारतीय बाजारों को वैश्विक मानकों के और करीब ले जाता है। उन्होंने कहा, ÷सीएएस बाजार की माइक्रोस्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा सुधार है और हम इसके पीछे मजबूती से खड़े हैं। दुनिया के कई प्रमुख बाजार पहले से इस व्यवस्था को अपना चुके हैं। जापान ने इसे 2024 में लागू किया, जबकि हांगकांग, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी यह प्रणाली मौजूद है। सेबी प्रमुख ने बताया कि क्लोजिंग प्राइस का उचित निर्धारण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर विभिन्न शेयर सूचकांकों, पैसिव निवेश उत्पादों और म्यूचुअल फंडों की नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) तय होती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ा फोकस इस नई व्यवस्था में बाजार सहभागिता बढ़ाने पर है। उनके अनुसार, अधिक से अधिक निवेशकों, ब्रोकरों और बाजार प्रतिभागियों को इस प्रणाली को समझने और इसमें भाग लेने की आवश्यकता है। पांडे ने कहा, ÷कई ब्रोकरों ने संकेत दिए हैं कि भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। सीएएस एक पूरी तरह पारदर्शी बाजार व्यवस्था है, जहां कीमतों का निर्धारण खुली प्रक्रिया के जरिए होता है। इसमें हर गतिविधि दिखाई देती है और अंत में एक निष्पक्ष मूल्य सामने आता है।

वैष्णो देवी में बैटरी कार सेवा शुरू, हर दिन 21 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे मां के दरबार

कटड़ा। मौसम में सुधार होने के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने सुबह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बैटरी कार मार्ग को फिर से खोल दिया। मार्ग खुलते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली और बैटरी कार सेवा सुचारू होने से भवन की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली ।कटड़ा और आसपास के इलाकों में धूप खिली रही, हालांकि त्रिकुटा पर्वत पर बादल छाने के कारण हेलिकॉप्टर सेवा बीच-बीच में प्रभावित हुई। इसके बावजूद यात्रा के अन्य सभी प्रमुख मार्ग खुले रहे और घोड़ा, पिट्ठू, पालकी जैसी सेवाएं भी लगातार मिलती रहीं। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 16 हजार से 21 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार शाम पांच बजे तक करीब 15 हजार और मंगलवार को लगभग 20 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई ।बरसात के मौसम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर श्राइन बोर्ड का आपदा प्रबंधन दल, प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हर स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि देश भर से आने वाले भक्त सुरक्षित और सुगम तरीके से मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें।

न्यूज विंडो

बदहाल सड़क, बाइक से उछलकर गिरी महिला को मिनी ट्रक ने कुचला

बंगलूरू। बंगलूरू ।में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के पास अनंतनगर मेन रोड पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां खराब सड़क के कारण ब्रेक लगने से दोपहिया वाहन फिसल गई, इस दौरान बाइक पर पीछे बैठी 32 वर्षीय महिला मेधा गिर गई ।इस दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक मिनी मालवाहक वाहन ने महिला को कुचल दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने महिला मेधा को मृत घोषित कर दिया ।दरअसल, EPF कार्यालय में कार्यरत मेधा अपने सहकर्मी के साथ दोपहिया वाहन पर सिंगासंद्रा की ओर जा रही थी, इसी दौरान कीचड़ भरे टूटी सड़क पर एक पैदल यात्री को बचाने के लिए कार और बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगाए।

कावेरी विवाद पर कर्नाटक बंद: कन्नड़ संगठनों का राज्यव्यापी प्रदर्शन

बंगलूरू। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है। इस दौरान कोप्पल में लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु नंबर के ट्रकों के चालकों को गुलाब दिए। उन्होंने चालकों से कहा कि कावेरी का पानी छोड़ने को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक को 'उकसाने' की कोशिश न करें ।यह प्रदर्शन कोप्पल तालुक के हिटलनाल टोल गेट पर हुआ। यह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। कर्नाटक बंद के तहत केरावे युवा सेना के नेता विजयकुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु नंबर के ट्रकों को रोका। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक चालकों से भिड़ने के बजाय उन्हें गुलाब दिए। यह गुलाब देना एक प्रतीकात्मक तरीके से विरोध जताने का हिस्सा था। फूल देते हुए विजयकुमार ने ट्रक चालकों से कहा, हम शांति पसंद करने वाले लोग हैं। हमें उकसाने की कोशिश न करें। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। उन्होंने कावेरी जल नियमन समिति यानी सीडब्ल्यूआरसी के एक निर्देश का विरोध किया।

विधायक प्रशांत किशोर ने बताया प्लान, कहा- बांकीपुर में बिना चोरी के होगा काम

पटना। जनसुराज के सूत्रधार व बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर बुधवार को बोरिंग कैनाल रोड में आभार सभा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम, थाना आदि से शिकायत है, तो जनसुराज कार्यालय में आकर शिकायत करें ।उन्होंने कहा कि विधायक से संबंधित किसी भी काम में एक रुपये की चोरी नहीं होने दी जाएगी। तीन महीने में बांकीपुर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा, जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है और 1100 की पेंशन नहीं मिले। सभी को निर्धारित राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रशांत ने कहा कि बांकीपुर में रहने वाले 70 प्रतिशत लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस कम कैसे हो, इसके लिए अगले साल मार्च तक प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ बैठकर एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी, ताकि जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कुछ आर्थिक राहत मिलने लगे। दूसरी आभार सभा मीठापुर में की गई।

डीजीसीए को पायलटों के ड्रग-टेस्टिंग नियमों में बदलाव का आदेश

अब जागी सरकार, कड़े होंगे सुरक्षा नियम, एयर इंडिया को चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने एअर इंडिया को संचालन और निगरानी में सुधार करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी लेने की कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन नियामक डीजीसीए को ड्रग-टेस्टिंग नियमों में जल्द से जल्द बदलाव करने और अनिवार्य जांच से गुजरने वाले विमानन कर्मचारियों का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकार ने विमानन नियामक को निर्देश दिया है कि जो लोग प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान लागू किए जाएं। वहीं, जिन कर्मचारियों के टेस्ट परिणाम किसी डॉक्टर द्वारा लिखी गई मेडिसिन के कारण पॉजिटिव आते हैं, उन्हें स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त मौके दिए जाएं।

क्रू की शिकायत पर पायलट की सफाई

गौरतलब है कि 4 अगस्त को 145 यात्रियों को ले जा रही एअर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान द्ध 2379 में बड़ी तकनीकी खराबी देखने को मिली थी। इस उड़ान के पायलट-इन-कमांड का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था ।सूत्रों के अनुसार, पायलट ने जांचकर्ताओं को बताया है कि व्यक्तिगत समस्याओं के कारण नींद की गोलियां खानी पड़ी थीं, इसी वजह से उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके अलावा, केबिन क्रू द्वारा शिकायत किए जाने के बाद विमान में पायलट के व्यवहार की भी कड़ी जांच की जा रही है।

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

जून में हुए एअर इंडिया के अहमदाबाद हादसे की अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, अब एअर इंडिया के साथ एक और बड़ी घटना हो गई, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। सरकार ने उड़ान AI 2379 की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है, दोषियों पर गाज गिरना तय है। उड्डयन सचिव समीर सिन्हा ने एअर इंडिया के शीर्ष प्रबंधन को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि एयरलाइन को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और जांच में दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

तकनीकी खराबी के कारण बाल-बाल बचा विमान

सरकार की नाराजगी है कि उड़ान द्ध 2379 बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची है। रिपोर्ट के अनुसार, जब विमान ओडिशा के ऊपर से गुजर रहा था, तब विमान के तीन हाइड्रोलिक सिस्टम, दरवाजों और एलिवेटर को लेकर एक के बाद एक कई चेतावनियां मिलने लगीं, जो विमान को ऊपर-नीचे ले जाने में मदद करता है।

दिल्ली दंगा मामले में 13 आरोपियों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया बरी

नई दिल्ली, एजेंसी

वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 आरोपितों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपितों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर सका।

अदालत ने उद्घोषित अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया में पुलिस की खामियों, कथित साजिश के पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और धुंधली सीसीटीवी फुटेज को फैसले में अहम माना ।मामले में अभियोजन का आरोप था कि आरोपितों ने दिल्ली दंगों के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए साजिश रची थी। हालांकि अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि कथित साजिश कब, कहां और किस तरह रची गई तथा उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। अदालत ने यह भी पाया कि केवल कुछ हथियारों की बरामदगी को कथित साजिश से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

उद्घोषित अपराधी घोषित करने में प्रक्रिया का पालन नहीं

मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ उद्घोषित अपराधी घोषित किए जाने की कार्रवाई से जुड़ा मुद्दा भी सामने आया। अदालत ने पाया कि इनमें से दो के खिलाफ की गई उद्घोषणा की कार्रवाई बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ले ली गई थी। वहीं, शेष छह आरोपितों के संबंध में पुलिस ने कानून के तहत जरूरी तीन चरणों की प्रक्रिया पूरी तरह नहीं अपनाई।

अदालत ने कहा कि अभियोजन के गवाह ने यह नहीं बताया कि आरोपित के निवास स्थान पर उद्घोषणा पढ़कर सुनाई गई थी। इसके अलावा घर पर उद्घोषणा चस्पा करने और उसे अदालत परिसर में लगाने की प्रक्रिया के संबंध में भी पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए। अभियोजन का कहना था कि आरोपित फरार थे और उनका शुरुआती तौर पर पता नहीं लगाया जा सका था। इसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए और उद्घोषणा की कार्रवाई शुरू हुई।

सीजेपी के सौरव दास के परिवार से पूछताछ केंद्र पर लगाया डराने का आरोप

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी पुलिस उनके घर पहुंची और उनसे परिवार से पूछताछ की। दास ने दावा किया कि 'केंद्र सरकार के कहने पर' उनके परिवार को डराया जा रहा है।

सौरव दास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि पुलिस को उनके घर जाने का आदेश किसने दिया। इसके पीछे वजह क्या थी। दास ने लिखा, दो घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस मेरे घर पहुंची और परिवार से कई तरह के सवाल किए। पुडुचेरी पुलिस परेशान क्यों कर रही है? इसका आदेश किसने दिया और किस मकसद से? क्या यह कानूनी प्रक्रिया है?

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन वाली सरकार उनके परिवार को 'डरा' रही है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के स्वभाव के मुताबिक नहीं है।

सुशांत सिंह राजपूत की बहन का बड़ा दावा, कहा- 'वो परेशान थे, उनके पास कुछ जानकारी थी'

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को लेकर कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या माना, जबकि कुछ लोगों ने इसमें किसी तरह की साजिश और गलत काम की आशंका जताई थी। सुशांत की बहन श्वेता लगातार अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग करती रही हैं।

हाल ही में एक इंटरव्यू में श्वेता ने कहा कि 6 साल बाद भी परिवार को यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था ।उन्होंने कहा, 'छह साल हो गए हैं, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि असल में क्या हुआ था ।पोस्टमार्टम कराने की

इतनी जल्दी क्यों थी ?वह कभी अपने कमरे को लॉक नहीं करते थे। फिर उनका कमरा अंदर से कैसे लॉक था ?ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं।'श्वेता ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि उस मामले में कुछ ठीक नहीं था। उनके मुताबिक, 'कुछ तो सही नहीं था। कुछ गलत था।'

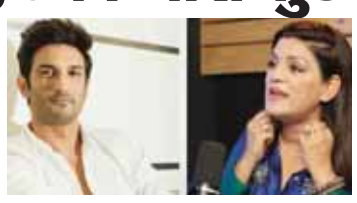

दिशा सालियान की मौत के बाद परेशान थे सुशांत

श्वेता ने यह भी दावा किया कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत काफी परेशान रहने लगे थे। दिशा सालियान सुशांत की मैनेजर थीं और मुंबई की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी ।श्वेता ने बताया कि दिशा की मौत के बाद सुशांत बार-बार कहते थे कि 'वे उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे।'उन्होंने कहा, 'दिशा सालियान की मौत के बाद वह बहुत परेशान थे। वह कहते रहते थे कि वे लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता। शायद उनके पास कोई ऐसी जानकारी थी, जिसे वह सामने लाने वाले थे। शायद कुछ ऐसा ही था।

मेट्रो एंकर — कैश कांड में जांच समिति ने तीनों आरोप सही माने, इस्तीफे के बाद अब जांच पर टिकी नजर

क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज होगा आपराधिक मामला?

नई दिल्ली, एजेंसी

जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में नकदी मिलने के मामले में जांच समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोप सही पाए हैं।

समिति के अनुसार वह नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। रिपोर्ट में साक्ष्यों की स्थिति में बदलाव और उन्हें सुरक्षित रखने में गंभीर चूक का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश होने के बाद अब सवाल है कि क्या उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा और क्या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

जस्टिस वर्मा अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया को लेकर कानूनी स्थिति अलग है। विशेषज्ञों की राय भी बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि इस्तीफे के बावजूद आपराधिक जांच का रास्ता खुला है, जबकि कुछ विशेषज्ञ संसदीय प्रक्रिया और इस्तीफे की स्थिति को लेकर अलग राय रखते हैं। फिलहाल समिति की रिपोर्ट अपने आप दोषसिद्धि नहीं है और आपराधिक अदालत की प्रक्रिया अलग होगी।

वहीं न्यायिक इतिहास में जस्टिस सीएस कर्णन का मामला अलग उदाहरण है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराकर छह महीने की सजा सुनाई थी। वह जेल जाने वाले पहले मौजूदा हाईकोर्ट जज बने थे। वर्मा मामले में अभी ऐसी कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं हुई है।

जस्टिस कर्णन को हुई थी छह महीने की सजा

जस्टिस सीएस कर्णन मद्रास और बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे। 2017 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की और फरवरी 2017 में उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक काम से रोक दिया। इसके बाद कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों के खिलाफ भी आदेश जारी किए। 9 मई 2017 को सात सदस्यीय पीठ ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई। 20 जून को उन्हें कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया। दिसंबर में सजा पूरी होने पर वे जेल से बाहर आए।

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में अब सबसे बड़ा सवाल क्या?

जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद 14 मार्च 2025 की रात सामने आया था। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद स्टोर रूम में अधजली नोटों की गड्डियां मिलने की बात सामने आई। इसके बाद आंतरिक जांच और फिर संसद की प्रक्रिया शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच के बाद तीनों आरोप सही माने। हालांकि, जस्टिस वर्मा अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे चुके हैं। अब बहस इस बात पर केंद्रित है कि समिति की रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ एफआईआर और आपराधिक जांच किस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगी। विशेषज्ञ इस मुद्दे पर अलग-अलग कानूनी राय रख रहे हैं। फिलहाल जेल जाने का फैसला किसी आपराधिक अदालत की आगे की कार्रवाई और निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया**
स्थानीय संपादक अनिल शर्मा* आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564